सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 200, नई दिल्ली । रविवार, 29 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 दो दिन में सड़कों की मरम्मत और निमार्ण कार्य की स्टेटस रिपोर्ट...
06 मानव मन की गहराइयों की खोज
08 गीता के उपदेशों और श्रीकृष्ण के जीवन से प्रेरणा

ये दिल्ली है मेरे यार ! सड़कें कम गड्ढे ज्यादा

पांच मिनट का सफर 20 में होता पूरा....

दिल्ली वैसे तो देश की राजधानी कही जाती है लेकिन यहां की सड़कों का जो हाल इस मानसून में हुआ है। वैसा बुरा हाल शायद कभी नहीं हुआ होगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या अधिकारियों की लापरवाही को मुख्य कारण मान सकते हैं? बता दें लोक निर्माण विभाग के पास दिल्ली में 1260 किलोमीटर सड़कें हैं।

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों का इस मानसून में जितना बुरा हाल हो गया है, शायद ही कभी हुआ होगा। सड़कों पर खतरनाक गड्ढे हो गए हैं। कई जगह तो सड़कों पर ऊपर की लेयर ही गायब है। इसलिए दिल्ली में सड़कों से गुजर रहे हैं तो संभल कर चलें।

खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए सलाह है कि कहीं ऐसा न हो कि आप का वाहन अचानक गड्ढों में जाए और आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। यह खराब हालत कुछ मानसून के कारण तो कुछ अधिकारियों की लापरवाही से हुई है। छोटी सड़कों का ही नहीं मुख्य मार्गों का भी बुरा हाल है।

लोक निर्माण विभाग के पास 1260 किलोमीटर सड़कें

बारापुला, रानी झांसी फ्लाईओवर सहित कई अन्य फ्लाईओवरों पर भी हैं गड्ढे। सड़कों पर चल रहीं परियोजना स्थलों के आसपास भी बुरा हाल है। मगर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कागजी खानापूर्ति में लगे हैं। उनके हिसाब से कार्रवाई पूरी है और काम भी हो रही है मगर समस्या बिकराल होती जा रही है।

लोक निर्माण विभाग के पास दिल्ली में 1260 किलोमीटर सड़कें हैं। सही मायनों में यही दिल्ली की मुख्य सड़कें हैं अगर नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली कैंट इलाके को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी सड़कें इसी विभाग के पास हैं। सड़कों पर गड्ढों से लोगों के वाहन खराब हो रहे हैं, वहीं सड़कों पर जाम भी लग रहा है।

पुलिस ने टूटी सड़क से लोगों को बचाने के लिए लगाए बैरीकेड्स

टूटी सड़कों से लोगों को बचाने के लिए यातायात पुलिस भी लगातार लोगों को जागरुक कर रही है। सड़कों पर गड्ढों के बारे में बता रही है। कई जगह पुलिस ने टूटी सड़क से लोगों को बचाने के लिए अपने बैरीकेड्स तक लगाए हुए हैं।

स्थिति पर गौर करें तो रानी झांसी फ्लाईओवर पर अगर करोल बाग की ओर से चढेंगे तो चढ़ने से पहले ही आप को जाम में फंसना पड़ेगा, क्योंकि उसी स्थान पर करीब 20 मीटर में गहरे गड्ढे हैं।अगर जाम नहीं है तो अचानक तेज रफ्तार में वाहन के पहुंचने पर खास कर दो पहिया के दुर्घटना का पूरा खतरा है। क्योंकि इससे पहले सड़क की स्थिति अच्छी है।

इसी तरह बारापुला एलीवेटेड कारिडोर पर सराय काले खां की ओर से चढ़कर जब आईएनए के पास उतरते हैं तो उससे कुछ पहले काफी गड्ढे हैं, यहां पहुंचकर वाहनों के एकाएक ब्रेक लगते हैं। इतना ही नहीं निर्माण स्थलों के आसपास यह हाल है कि पांच मिनट का रास्ता वाहन चालक 15 मिनट में पूरा कर पाते हैं। लोक निर्माण विभाग का इस ओर बार बार ध्यान दिलाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है।

पांच मिनट का सफर 15 से 20 मिनट में होता है पूरा

शहीद मंगल पांडे मार्ग पर भजनपुरा से लेकर यमुना विहार तक मेट्रो द्वारा बनाए जा रहे डबल डेकर फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर भयंकर गड्ढे हैं। इससे जाम लगता है और अच्छा मार्ग वाहन चालकों के लिए दुखदाई हो जाता है। सिग्नेचर ब्रिज की ओर से आने वाले वाहन चालक आधे-आधे घंटे तक जाम में फंसते हैं।

दूसरा मामला इसी मार्ग पर आगे जाकर नंद नगरी और सुंदर नगरी के बीच का है। यहां लोक निर्माण विभाग फ्लाईओवर बना रहा है। यहां करीब डेढ़ किलोमीटर इलाके में बहुत-बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, कई जगह सड़क ही गायब है। यहां पांच मिनट का सफर 15 से 20 मिनट में पूरा होता है।

विभाग का कहना है कि मानसून के कारण सड़क नहीं बनाई जा पा रही है। जबकि सही बात यह है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हालात पैदा हुए हैं। अधिकारियों का यहां काम करा रही कंपनी पर नियंत्रण नहीं है या हों कहें कि अधिकारयों ने कंपनी को जनता को परेशान करने की छूट दे रखी है। विशेषज्ञों की मानें तो सड़क अगर नहीं बनाई जा सकती है तो गड्ढे तो भरे ही जा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है।

नोएडा डिपो ने प्रदेश में गाड़ा परचम, परिवहन निगम की रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 20 क्षेत्रों में नोएडा डिपो ने पहला स्थान हासिल किया है। गाजियाबाद दूसरे और चित्रकूटधाम तीसरे स्थान पर रहा। ग्रेटर नोएडा डिपो ने प्रदेश के 108 डिपो में से पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे डिपो कर्मचारियों का योगदान सराहनीय है। रैंकिंग में पहला दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले डिपो के अधिकारियों को प्रोत्साहन किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा को परिवहन निगम के 20 क्षेत्रों में प्रदेश में रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। रैंकिंग में गाजियाबाद को दूसरा व चित्रकूटधाम को तीसरा तीसरा स्थान मिला है। वहीं प्रदेश के 108 डिपो में से ग्रेटर नोएडा डिपो को रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। रैंकिंग में दूसरे स्थान पर लखनऊ रहा।

निगम की मुख्यालय समिति द्वारा जुलाई महीने में किए गए मूल्यांकन में यह रैंकिंग दी गई है। मासिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रबंधन और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डिपो हेतु संचालन के चार प्रतिफलों आय प्रतिदिन, बस उपयोगिता, ईंधन औसत व लाभ प्रतिबस प्रतिदिन के आधार पर चयन किया जाता है।

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डिपो और तीन सेवा प्रबंधक का चयन

सेवा प्रबंधक हेतु संचालन के चार प्रतिफलों ऑन रोड प्रतिशत, बस उपयोगिता, ईंधन औसत और व्यय प्रतिबस प्रतिदिन में निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्धि और गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि के आधार पर मूल्यांकन करते हुए प्राप्त कुल अंकों के आधार पर रैंकिंग अनुसार प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ तीन क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डिपो और तीन सेवा प्रबंधक का चयन किया गया है।

रैंक पाने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र

चयन समिति में मुख्यालय के एमडी, एडिशनल एमडी, सीजीएम व जीएम इसका चयन करते हैं। परिवहन निगम के प्रतिफलों में बढ़ातेरी के लिए निगम मुख्यालय द्वारा पिछले साल फरवरी में मासिक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। रैंकिंग में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले डिपो के अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

18 रूट पर चलती है बसें

ग्रेटर नोएडा डिपो द्वारा 18 रूटों पर बसों का संचालन किया जाता है। मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, आगरा, कासगंज, कायमगंज, अलीगढ़ व अन्य रूटों पर ग्रेटर नोएडा डिपो से बसों का संचालन किया जाता है।

डिपो के कर्मचारियों के योगदान से यह संभव हो पाया है। भविष्य में भी अपेक्षा है कि इसी तरह कार्य करते हुए डिपो को उन्नति की ओर ले जाएंगे। - अनिल कुमार शर्मा, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ग्रेटर नोएडा डिपो

अब नहीं चलेगा खराब फास्टैग का बहाना, चुकाना पड़ेगा हाईवे का बकाया टोल, NHAI ने बनाई फुल-प्रूफ योजना

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जल्द ही, दोषपूर्ण या ब्लैक लिस्टेड फास्टैग के कारण टोल वाले हाईवे सेक्शन (राजमार्ग खंड) का इस्तेमाल करने के बाद लंबे समय तक टोल शुल्क का भुगतान नहीं करना संभव नहीं होगा। टोल शुल्क का ऐसा भुगतान नहीं करना, वाहन पोर्टल और एप पर दिखाई देगा, जैसा कि ट्रैफिक चालान बकाया के मामले में होता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) (एनएचएआई) ने सड़क परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह पंजीकृत वाहनों के संग्रह Vahan (वाहन) प्रणाली में बदलाव करे। ताकि बिना फास्टैग या दोषपूर्ण/ब्लैक लिस्टेड टैग वाले वाहनों से बकाया टोल वसूला जा सके। इसने बकाया राशि प्रदर्शित करने के लिए वाहन पोर्टल में एक सेक्शन - 'अनपेड यूजर फीस बकाया' जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया है।

एनएचएआई ने कहा कि वाहन पोर्टल पर वाहन मालिक के लॉग इन करने पर बकाया राशि और साक्ष्य के तौर पर वाहन की तस्वीर दिखाई जाएगी।

एनएचएआई के प्रस्ताव के मुताबिक, ऐसे वाहन मालिकों को बकाया राशि चुकाए बिना पंजीकरण स्थानांतरित करने या एनओसी और फिटनेस प्रमाणपत्र हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाहन मालिकों के पास सात दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने या नोटिस पर आपत्ति जताने का विकल्प होगा।

यह प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है क्योंकि एनएचएआई ने कुछ हिस्सों पर टोल लगाने की फ्री-फ्लो सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट-आधारित टोलिंग प्रणाली के पूरी तरह से लागू करने से पहले इसका विस्तार किया जाएगा।

सैटेलाइट आधारित प्रणाली में, टोल बूथ या बैरियर की जरूरत के बिना वाहनों को सुचारू रूप से चलने की अनुमति दी जाती है। यह वाहनों की ऑटोमैटिक पहचान करने और टोल वसूलने के लिए कैमरे, सेंसर और नंबर प्लेट पहचान का इस्तेमाल करता है।

एनएचएआई ने प्रस्ताव दिया है कि जब कोई वाहन बिना फास्टैग या ब्लैक लिस्टेड टोल प्लाजा से गुजरता है, तो उसका कंट्रोल रूम एक नोटिस तैयार करेगा और उसे वाहन पोर्टल पर भेजेगा।

एक अधिकारी ने कहा, "बाद में, इसे बीमा के रिन्युअल (नवीनीकरण) से जोड़ने जैसे और विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सिस्टम को नुकसान न पहुंचा सके।"

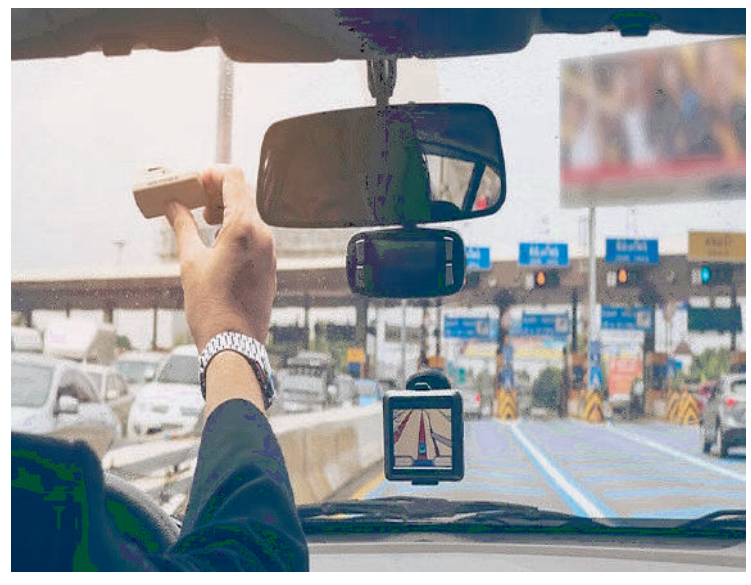

गाजियाबाद में बनने वाले बस अड्डे को लेकर आया बड़ा अपडेट, लोगों को बहुत जल्द मिलेगा फायदा

गाजियाबाद में बनने वाली बस अड्डे को लेकर नई जानकारी सामने आई है। जिसके तहत 15 पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया है। जब तक इसकी कटाई नहीं हो रही थी तब तक बस अड्डे का कार्य प्रभावित हो रहा था। बता दें इस बस स्टॉप को बनाने में 61 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। इसके बन जाने के बाद लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

साहिबाबाद। गाजियाबाद बस अड्डे के परिसर में पेड़ों के काटने का कार्य शुरू हो गया है। अगले एक सप्ताह में सभी पेड़ों को काटने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि पेड़ कटने के बाद निर्माण कंपनी तेजी से कार्य करा सकेगी। गाजियाबाद बस अड्डे का निर्माण पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के अंतर्गत ओमेक्स कंपनी कर रही है। बस अड्डे का निर्माण हवाई अड्डे की तर्ज पर करीब 61 करोड़ के बजट से हो रहा है। अड्डा के परिसर में छोटे-बड़े करीब 15 पेड़ होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा था। कंपनी ने परिवहन निगम से पेड़ों को कटवाने के लिए कहा था। इस पर परिवहन निगम ने पेड़ों को कटवाने के लिए वन विभाग से अनुमति लेने के साथ ही पेड़ों की कीमत लगवाई थी। इसके बाद वन विभाग के मेरठ स्थित कार्यालय में पेड़ों की बोली लगाई गई थी।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली में 7 अक्टूबर से चलेगा विशेष कैंपेन, फॉलो नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर व्यक्तियों या कंपनियों को 14 नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एंटी डस्ट कैंपेन के 14 नियमों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को इन सभी 14 नियमों का पालन हर दिल्लीवासी को करना है। उन्होंने कहा कि मेरी दिल्ली के लोगों से विनती है, जो लोग व्यक्तिगत कंस्ट्रक्शन निर्माण करा रहे हैं, या कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन करा रही हो या कोई सरकारी विभाग निर्माण कर रहा हो, सभी एंटी डस्ट कैंपेन के इन नियमों का पालन जरूर करें।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण में 3 मुख्य फैक्टर हैं- पहला डस्ट पॉल्यूशन, दूसरा व्हिकल पॉल्यूशन और तीसरा बायो मास पॉल्यूशन। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार 7 अक्टूबर से 7 नवम्बर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी। उन्होंने कहा कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत 14 नियमों को फॉलो करना होगा जो 7 अक्टूबर से इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा तो उनके खिलाफ हमारी टीम सख्त एक्शन लेगी।

कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा: गोपाल राय

गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही साइट्स पर एंटी स्मॉग गन नहीं लगाई जाती है तो भी कंपनियों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्री के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों और कृषि मंत्रियों की मीटिंग होती थी जो इस साल अभी तक नहीं हुई है।

पिछले साल पंजाब में 50% कम पराली जली: गोपाल राय

गोपाल राय ने कहा कि मेरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्री से अपील है कि इस मीटिंग को तुरंत कराया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब की AAP सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने दो साल में इतने प्रयास किये हैं कि पिछले साल पंजाब में 50% कम पराली जली है। केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए उसे 100% पावर कंट्रोल चाहिए लेकिन उन्हें जिम्मेदारी 0% चाहिए। मुझे भरोसा है कि BJP की केंद्र सरकार जल्द ही पर्यावरण के मुद्दे पर मीटिंग बुलाएगी।

सावन में जरूर करें उज्जैन के इन शिव मंदिरों के दर्शन, प्राप्त होगी भोलेनाथ की कृपा

कई लोग सावन के सोमवार को भगवान शिव के ऐतिहासिक मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान शिव के ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, जो चमत्कारिक हो तो आप उज्जैन आ सकते हैं।

हर साल सावन के महीने में शिव भक्त शिवालयों में जाकर भगवान शिव का विधि-विधान से पूजा-अर्चना और दर्शन करते हैं। माना जाता है कि सावन महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए कई लोग सावन के सोमवार को भगवान शिव के ऐतिहासिक मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान शिव के ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, जो चमत्कारिक हो तो आप उज्जैन आ सकते हैं। उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। यहां पर आपको भगवान शिव को समर्पित तमाम मंदिर मिलेंगे। इन मंदिरों में दूर-दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको उज्जैन के दो ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको सावन महीने में दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए।

महाकालेश्वर मंदिर

उज्जैन के फेमस मंदिरों की बात की जाए, तो सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर का नाम आता है। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर आते हैं। बाबा महाकाल का यह मंदिर उज्जैन के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। यहां पर हर रोज बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर एक विशाल रूद्रसागर झील से घिरा है। रोजाना बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। सावन के महीने में यहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है।

भस्म आरती का समय- सुबह 04:00 बजे से 07:00 बजे तक
दर्शन- सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
शाम - 06:00 बजे से 07:00 बजे तक
रात्रि पूजन समय- 08:00 बजे से रात 10:00 बजे तक

काल भैरव मंदिर

बता दें कि काल भैरव को भगवान शिव को क्रोधित स्वरूप माना जाता है। सावन के महीने में यहां पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। मान्यता के अनुसार, जो भी भक्त सावन के महीने में भगवान काल भैरव के सच्चे मन से दर्शन करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर का इतिहास करीब 6 हजार साल पुराना बताया जाता है। इस काल भैरव मंदिर में प्रतिमा को मदिरा चढ़ाई जाती है और इस मंदिर को बेहद चमत्कारी माना जाता है। बताया जाता है कि भगवान को जिस बर्तन से मदिरा चढ़ाई जाती है, वह गायब हो जाता है। हालांकि यह कैसे होता है इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है।

समय- मंदिर सुबह 06:00 बजे से रात 09:00 बजे तक खुला रहता है।

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से आप भी खरीद सकते हैं बेहद कम कीमत में लैपटॉप

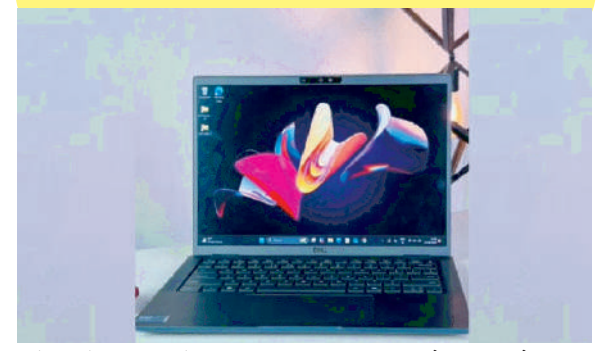

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2024 सेल में एक अच्छा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं जो 40 हजार की रेंज में हो, तो अमेजन पर इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गजब डील्स हैं। लेकिन सही लैपटॉप का चुनाव करना भी जरूरी है।

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2024 सेल सभी मेंबर्स के लिए जारी है। गुरुवार को प्राइम मेंबर्स के लिए शुरू हुई ये सेल शुक्रवार को सभी मेंबर्स के लिए लाइव हो चुकी है। सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में स्मार्टफोन से लेकर मोबाइल फोन के साथ आने वाली एक्सेसरी, ईयरबड्स, स्मार्टवॉच जैसे प्रोडक्ट्स पर आकर्षक छूट दी जा रही है। स्मार्टफोन्स इस सेल के हाइलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स कहे जा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप पर भी कंपनी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है।

अगर आप भी अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2024 सेल में एक अच्छा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं जो 40 हजार की रेंज में हो, तो अमेजन पर इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गजब डील्स हैं। लेकिन सही लैपटॉप का चुनाव करना भी जरूरी है। जैसे कि रैम, ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर देखकर ही लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो अप आपको अमेजन सेल में 40 हजार रुपये से कम के बेस्ट लैपटॉप के बारे में बताने जा रहे हैं।

सेल में कंपनी लैपटॉप पर बैंक डिस्काउंट समेत एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। साथ ही नो-कॉस्ट EMI विकल्प भी है। Dell, Acer, HP और Lenovo जैसे ब्रांड्स सेल में शामिल हो रहे हैं और इन पर 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट उपलब्ध है डेल 15 को सेल में इस वक्त 27,740 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Acer Aspire Lite को 25,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 13th Gen Intel Core i3-1305U Soc लगा है। इसका लिस्ट प्राइस 50,990 रुपये है। इस हिसाब से इस लैपटॉप पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। Amazon सेल में एसबीआई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीद पर 10 प्रतिशत का इस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। 24 महीने के नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी खरीद के लिए उपलब्ध हैं।

रोजाना केला खाना किसी वरदान से कम नहीं है, मिलते हैं जबरदस्त फायदे

फिट रहने के लिए हम सभी क्या नहीं करते हैं लेकिन फिर भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। क्योंकि हमारी जीवनशैली बेहद ही खराब है। गलत खानपान की वजह से शरीर स्वस्थ नहीं होता बल्कि सुस्त हो जाता है। इसलिए रोजाना केला खाना बहुत जरुरी है। केला में विटामिन बी6, विटामिन सी और पोटेशियम का समृद्ध गुण होते हैं।

अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो डाइट में बस एक चीज शामिल कर लें। फिर देखें कैसे आपके शरीर में चमत्कार होगा। क्या आपको पता हैं कि विश्व भर के लोग सबसे ज्यादा कौन-सा फल खाते हैं? बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने फल है केला। केला में मिनरल और फाइबर से भरपूर होता है और इसके अनगिनत फायदे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केला में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज जैसे शर्करा होते हैं। ये सभी पदार्थ तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि केला को खिलाड़ियों और सक्रिय जीवनशैली जीने वालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें काफी मात्रा में फाइबर, खासकर पेक्टिन होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार होता है। यह स्वादिष्ट फल विटामिन बी6, विटामिन सी और पोटैशियम का भरपूर स्रोत है। केले में कई एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं।

पाचन तंत्र बेहतर होता है

यह हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। केले में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज के साथ-साथ पेट के अल्सर को कम करने में मदद करता है।

झुर्रियां कम होती है

इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है, जो सेरोटोनिन में बदल जाता है। सेरोटोनिन मूड को ठीक करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। केले में विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। इसमें एंटी-एजिंग गुण भी होते हैं।

किडनी की कार्यप्रणाली बेहतर होती

केला का सेवन किडनी की कार्यप्रणाली को भी बेहतर बनाता है क्योंकि इसमें पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है और यह किडनी स्टोन के खतरे को कम करता है। इसमें मौजूद उच्च फाइबर अधिक खाने से रोकता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वजन कम करने में मदद करता है।

हड्डियां मजबूत रहती है

विटामिन बी6 और पोटैशियम के अलावा केले में कुछ मात्रा में कैल्शियम भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। नियमित रूप से केला खाने से हड्डियों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है।

इम्यूनिटी मजबूत होती है

केला में विटामिन सी और बी6 होता है, जो कई बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। कई शोधों से पता चला है कि मधुमेह के रोगी भी केला खा सकते हैं क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।

स्विट्जरलैंड का मजा भारत में लेना हैं, तो इन 6 जगहों पर जरुर घूमने जाएं

भारत में कई खूबसूरत हिल स्टेशन मौजूद हैं। खूबसूरती में ये हिल स्टेशन स्विट्जरलैंड को टक्कर देते हैं। अगर आप भारत के स्विट्जरलैंड की जगहों पर घूमना चाहते हैं, तो आप इन हिल स्टेशन पर घूमने जरुर जाएं। यहां की सुंदर वादियां देखकर आपका मन खुश हो जाएंगा। जानें भारत के इन हिल स्टेशन के बारे में जो स्विट्जरलैंड से कम नहीं हैं।

अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो इन जगहों को घूमने से आपका दिल भर जाएगा। भारत में कुछ जगहें 'मिनी स्विट्जरलैंड' के नाम से मशहूर हैं। अगर आप अपनी तनावपूर्ण जिंदगी से ब्रेक लेना चाहते हैं तो आपको इन जगहों की खूबसूरत वादियों के बीच कुछ दिन बिताने का प्लान जरूर बनाना चाहिए। अगर आपका बजट आपको स्विटजरलैंड जाने की इजाजत नहीं दे रहा है तो आप इन जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं जहां स्विटजरलैंड की झलक मिलती है।

ओली, उत्तराखंड

यह हिल स्टेशन उत्तराखंड में स्थित है। औली को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सर्दियों में यह स्थान बर्फ से ढका रहता है और यहां पर देश-विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। औली भारत के टॉप स्कीइंग स्थलों में से एक है; इसमें बर्फ से ढके पहाड़, जो इसे सर्दियों के मौसम के दौरान साहसिक चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है।

कश्मीर, जम्मू-कश्मीर

कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' कहा जाता है। कश्मीर घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहां चमचमाती झीलें और नदियां, हरे-भरे घास के मैदान और बर्फ से ढके पहाड़ों का नजार देखकर दिख खुश हो जाएगा जाएगा। आपको बता दें कि, सर्दियों में यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले वंडरलैंड में बदल जाता है, जिससे इसकी तुलना यूरोप के अपने स्विट्जरलैंड से की जाती है।

मुनस्यारी

मुनस्यारी को मिनी स्विट्जरलैंड के साथ-साथ उत्तराखंड की आत्मा भी कहा जाता है। घने जंगल और बर्फीली चोटियों से घिरा यह हिल स्टेशन आपकी यात्रा को शानदार बनाता है।

खजियार, हिमाचल प्रदेश

खज्जियार अपने लुभावने दृश्य के साथ पर्यटकों के लिए बेहद शानदार जगह है। यहां पर मौजूद हरी घास के मैदान, घने देवदार के जंगल, बीच में शांत झील और ऊंचे-ऊंचे पर्वत। डलहौजी के पास का यह शहर 'भारत का मिनी स्विट्जरलैंड' के रूप में जाना जाता है और आप जैसे नेचर लवर को लिए इसे अवश्य देखना चाहिए।

कौसानी

उत्तराखंड में स्थित कौसानी हिल स्टेशन का नजारा वाकई देखने लायक है। मंदिरों से लेकर झरनों और गुफाओं तक, आप यहां कई जगहें देख सकते हैं। इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।

ऑफिस गरबा-डांडिया नाइट में दिखना चाहते हैं स्टाइलिश तो इन आउटफिट्स को जरुर ट्राई करें

नवरात्रि शुरु होने में दिन ही कितने रह गए है। नवरात्रि त्योहार शुरु होते ही जगह-जगह गरबा और डांडिया नाइट की कार्यक्रम होते हैं। अगर आपके ऑफिस में भी डांडिया नाइट का आयोजन होता है और आप भी महफिल की जान बनना चाहती है तो आप भी इन आउटफिट्स को जरुर ट्राई करें।

नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़े ही उत्साह से बनाया जाता है। पूरे भारत में मां दुर्गा के पंडाल लगते हैं और गरबा-डांडिया नाइट का अयोजन होता है। इस दौरान महिलाएं लहंगा चोली ही पहनना पसंद करती हैं। हांलाकि जब ऑफिस में गरबा-डांडिया नाइट का आयोजन होता है तो महिलाएं कंफ्यूज होती है कि वह क्या पहनें। इस दौरान आप फ्यूजन आउटफिट्स पहन सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ यूनिक आउटफिट्स, जिसे आप डांडिया और गरबा नाइट में पहन सकते हैं।

जींस पर पहनें साड़ी

आजकल जींस के ऊपर साड़ी पहनने का स्टाइल काफी चल रहा है। कई एक्ट्रेसेस भी इस स्टाइल को अपना चुकीं हैं और आप भी इस ट्रेंड को अपना सकते हैं। परफेक्ट वेस्टर्न लुक पाने के लिए आप ये आउटफिट जरुर ट्राई करें।

गुजराती स्कर्ट के साथ शर्ट

अगर आप भी ऑफिस की गरबा-डांडिया नाइट की महफिल लूटना चाहती हैं, तो आप गुजरात स्कर्ट के साथ आप शर्ट जरुर पहने। आप व्हाइट शर्ट नॉट बांधकर काफी अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही आप कलरफुल मैचिंग स्कर्ट भी पहन सकते हैं। साथ ही आप सिल्वर जूलरी कैरी करें। इस लुक में सिल्वर नेकपीस और ईयररिंग्स अच्छे लगेंगे। आप बोहो लुक के लिए नोजपिन भी लगा सकते हैं।

धोती पैंट और पेपलम कुर्ती

डांडिया-गरबा नाइट के लिए धोती पैंट और पेपलम कुर्ती भी एक बेहतरीन विकल्प है। इसको आप ऑफिस में होने वाले फंक्शन के लिए कैरी कर सकते हैं। इस प्रकार के आउटफिट में आपको ट्रेंडी और कम्फर्टेबल लुक मिलेगा। इस आउटफिट के साथ आप झुमके कैरी कर सकते हैं।

बांधनी साड़ी

अगर आप ऑफिस के गरबा-डांडिया नाइट में सबसे बेहतरीन दिखना चाहते हैं, तो आप ऑफिस के फंक्शन में इस तरह की साड़ी को कैरी कर सकते हैं। इस साड़ी में आप क्लासी लुक दिखता है। जूलरी पहनकर आप एकदम खूबसूरत नजर आएंगे।

एमसीडी आयुक्त दो दिन में सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य की स्टेटस रिपोर्ट सौंपें- डॉ. शैली ओबेरॉय

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली की महापौर डॉ. शैली ओबेरॉय ने सड़कों की सही देखभाल न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को सड़कों के रखरखाव और निर्माण कार्य से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी दो दिन के अंदर साझा करने का सख्त निर्देश दिया है। मेयर ने सड़कों की खराब हालत पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि अगर इसमें और देरी हुई, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है।

महापौर डॉ. शैली ओबेरॉय ने वित्त वर्ष 2024-25 में सड़क परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए बजट, कुल खर्च और शेष धनराशि की एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

इस संबंध में महापौर डॉ. शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली की अधिकांश कॉलोनियों में एमसीडी की सड़कें बहुत खराब हालत में हैं। इससे न केवल दिल्ली के निवासियों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है, बल्कि गड्ढों के कारण सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। इसके अलावा, टूटी सड़कों के कारण सड़क पर धूल भी बढ़ रही है, जो दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है।

राष्ट्रीय राजधानी में एमसीडी की सड़कों के रखरखाव और निर्माण के नियमित काम भी समय पर नहीं किए जा रहे हैं। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन कार्यों को करने में किसी भी तरह की देरी से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने कहा है कि एमसीडी ने सड़कों के रखरखाव के लिए 1,000 करोड़ रुपए और मेयर के विवेकाधीन कोष के तहत 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर रखा है, जिसे चालू वित्त वर्ष 2024-25 में एमसीडी सड़कों के सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह दो दिन के अंदर यानि सोमवार, 30 सितंबर को शाम 5 बजे तक, एमसीडी की सड़कों के रखरखाव और निर्माण की स्थिति की जानकारी दें। विशेष रूप से-

- वित्त वर्ष 2024-25 में सड़क परियोजनाओं के लिए किस-किस बजट हेड के तहत धन आवंटित किया गया है और अब तक कितना खर्च हुआ है?

- यदि एमसीडी सड़कों के रखरखाव या निर्माण कार्य के लिए किसी भी बजट हेड से पैसा खर्च नहीं किया गया है, तो इसका कारण बताएं।

चालू वित्त वर्ष में मैंने मेयर विवेकाधीन निधि से कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से प्रत्येक सड़क परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को परियोजना-वार साझा करें।

दिल्ली में कारोबार करना होगा अब और भी आसान, आतिशी सरकार निवेशकों को देगी 'सिंगल विंडो' की सुविधा

दिल्ली सरकार ने निवेशकों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम (एसडब्ल्यूएस) की शुरुआत की है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवेदनों की मंजूरी को सरल बनाने काम के बोझ को कम करने और क्षेत्र विशिष्ट सुधारों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य नियमों को और अधिक प्रभावी बनाना प्रोजेक्ट को समय सीमा में तेजी से पूरा करना है।

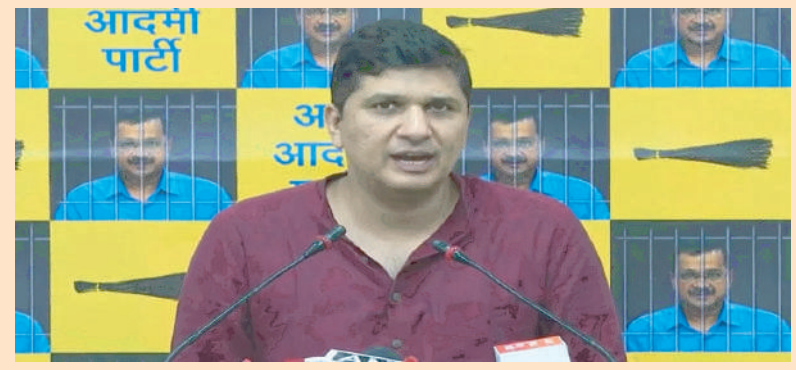

नई दिल्ली। *दिल्ली सरकार ने व्यवसायों के संचालन को सुव्यवस्थित और उनको गति देने के लिए एक और कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और लालफीताशाही को खत्म करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम (एसडब्ल्यूएस) की शुरुआत की है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवेदनों की मंजूरी को सरल बनाने, काम के बोझ को कम करने और क्षेत्र विशिष्ट सुधारों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।*

दिल्ली के उद्योग विभाग के अनुसार 12 विभागों की 59 सेवाओं को शामिल करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम का उद्देश्य नियमों को और अधिक प्रभावी बनाना और प्रोजेक्ट को समय सीमा में तेजी से पूरा करना और निवेशकों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करना है।

पिछले दशक में व्यापार सुधारों का मुख्य आधार

व्यापारिक नियम प्रक्रियाओं को सरल बनाना और ई-सेवा प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना, पिछले दशक में व्यापार सुधारों का मुख्य आधार रहा है। ऑनलाइन माध्यमों के जरिए देश में एक अधिक खुला और पारदर्शी व्यापारिक वातावरण बनाया गया है।

सिंगल विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म पर 59 सेवाएं जोड़ी गई

विभाग के अनुसार अब तक सिंगल विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म पर 12 संबंधित विभागों से 59 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इसमें विशेष रूप से, दिल्ली सरकार के 7 संबंधित विभागों से 37 सेवाएं शामिल की गई हैं, जिनमें श्रम विभाग, नगर निगम विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माप एवं तौल, दिल्ली जल बोर्ड, (पावर डिस्कॉम्स) टाटा पावर, बीएसईएस, बीआरपीएल और उद्योग विभाग शामिल हैं।

दिल्ली के सुंदर नगरी की गलियों से निकलकर 'सारेगामापा' शो में चमके कैफ, शीर्ष 20 प्रतिभागियों में बनाई जगह

दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके से निकलकर सारेगामापा के शीर्ष 20 प्रतिभागियों में जगह बनाने वाले कैफ की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। संगीत की प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। उनके पिता ने उन्हें संगीत की तालीम दी और आज वह अपने सपने को पूरा करने की राह पर हैं। जानिए कैफ के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी।

पूर्वी दिल्ली। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कोई भी बाधा प्रतिभा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। मेहनत, जुनून, दृढ़-निश्चय और लगन के दम पर उसे मंजिल मिल ही जाती है। ऐसे ही एक प्रतिभावान उभरते सितारे सुंदर नगरी इलाके में रहते हैं। जिन्होंने अपने पिता से संगीत की तालीम पाकर गायन के रियलिटी शो 'सारेगामापा' के शीर्ष 20 में जगह बना ली है।

उन्होंने शो में 'नैना ठग लेंगे' गीत की प्रस्तुति से अपनी आवाज का ऐसा जादू बिखेरा, जिससे शो के जज गुरु रंधावा, सचिन-जिगर, सचेत और परंपरा खुद को सीट से उठने से रोक नहीं पाए। सभी जजों ने सीट से उठकर तालियां बजाकर उनके गायन कौशल की सराहना की।

कैफ का परिवार मूल रूप से मेरठ निवासी

यह कहानी है सुंदर नगरी के एन-ब्लॉक निवासी मोहम्मद कैफ (18 वर्ष) की। कैफ अपने पिता इरफान अहमद, मां शन्नो, भाई सैफ अली, फैजल अली, जैद और बहन मुस्कान के साथ रहते हैं। परिवार मूल रूप से मेरठ के सरधना का रहने वाला है। कैफ ने सुंदर नगरी के जे-ब्लॉक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय से पिछले वर्ष 12वीं पास की है।

उनके पिता कभी इस्त्री करने, कभी दुकानों पर पैकिंग करने जैसे छोटे काम कर परिवार का पालण-पोषण करते हैं। पिता को गाने के अच्छा रियाज था। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी कि बच्चों को संगीत की तालीम दिला सकें। इसलिए उन्होंने घर पर ही कैफ को छह वर्ष की उम्र से संगीत सिखाना शुरू किया। साल 2019 में कैफ इंडियन आइडल में शीर्ष सौ में रहे। कई शो में अस्वीकृति का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस साल उन्होंने मेहनत के दम पर सारेगामापा में बेहतरीन प्रस्तुति देकर शीर्ष 20 में जगह बना ली है।

प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं कैफ

कैफ ने बताया कि उनका सपना है कि वह बड़े होकर बालीवुड प्लेबैक सिंगर बनें। सुखविंदर सिंह और अरिजीत सिंह को वह अपना आदर्श मानते हैं। सलमान खान से मिलने का सपना भी अभी अधूरा है।

पिता के सपने को पूरा कर रहे कैफ

इरफान ने बताया कि उनको बचपन से ही गाने का शौक था। लेकिन उनके पिता अनवर अहमद शिक्षक थे, तो वह चाहते थे कि उनका बेटा पढ़-लिखकर डाक्टर, इंजीनियर या अफसर बने। लेकिन गायक बनने के शौक के कारण पिता से छिपकर वह रेडियो पर मोहम्मद रफी को सुनकर रियाज किया करते थे। उन्होंने गायन में रुचि रखने वाले अपने पुत्र फैजल और कैफ को रियाज कराया। फैजल भी कुछ साल पहले एक रियलिटी शो में शीर्ष 30 में जगह बना चुके हैं। कैफ ने कहा कि पिता के सपने को पूरा करने की वह हर संभव कोशिश करेंगे।

गुरु साहिब का एक शब्द मन में बसाने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है: जसप्रीत सिंह करमसर

नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धर्म प्रचार विंग के चेयरमैन सरदार जसप्रीत सिंह करमसर ने कहा है कि गुरु साहिब का एक शब्द मन में बसाने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। आज जवड्डी टकसाल में 450 साला गुरु अमरदास जी का जोति जोत और गुरु रामदास जी की गुरता गद्दी को समर्पित विशेष सेमिनार को संबोधित करते हुए सरदार जसप्रीत सिंह करमसर ने उदाहरणों सहित बताया कि कैसे गुरु साहिब का एक शब्द मन में धारण करने से जीवन बदलता है। उन्होंने कहा कि जब मन में यह ठान लिया जाता है कि किसी की बुराई नहीं करनी है, तो हमारा जीवन के प्रति नजरिया बदल जाता है। इसी प्रकार जब हम मन में ठान लेते हैं कि अमृत वेले उठकर पाठ करना है, तो हमारा जीवन के प्रति नजरिया बदल जाता है। उन्होंने कहा कि यह गुरु साहिब की ही बख्शिश है कि ऱ्एक शब्द मेरे प्राण बसत हैऱ के सिद्धांत के मुताबिक हमारे जीवन में बदलाव आता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हर महीने 100 से अधिक कीर्तन दरबार होते हैं और लगभग इतने ही कथा एवं गुरमत समागम भी होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इन समागमों में आने वाले लाखों लोगों में से चुने हुए व्यक्तियों को भी गुरमत से जोड़ने में सफल होते हैं, तो इसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है। उन्होंने जवड्डी टकसाल के प्रबंधकों, खासतौर पर बाबा अमीर सिंह जी का यह प्रोग्राम करवाने पर धन्यवाद किया। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य सरदार हरजीत सिंह पप्पा और सरदार सरबजीत सिंह विरक भी उपस्थित थे।

डीडीए के 169 फ्लैटों के लिए आए 2000 आवेदन, धड़ाधड़ हुए बुक

डीडीए की आवासीय योजनाओं को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। 169 फ्लैटों के लिए 2000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) हरित और स्वच्छ दिल्ली को सुनिश्चित करने के लिए आवासीय क्षेत्र के आसपास हरित क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। आवासीय ब्लॉक को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय निकाय के सहयोग से सफाई व्यवस्था की जाएगी।

नई दिल्ली। रक्षाबंधन के अवसर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा शुरू की गई आवासीय योजनाओं को लेकर लोग रुचि दिखा रहे हैं। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि हरित और स्वच्छ दिल्ली को सुनिश्चित करने के लिए डीडीए आवासीय क्षेत्र के आसपास हरित क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। आवासीय ब्लॉक को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय निकाय के सहयोग से सफाई व्यवस्था की जाएगी।

डीडीए के अनुसार सस्ता घर और मध्यम वर्गीय आवासीय योजना के अंतर्गत 1200 से अधिक एलआईजी और 440 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बिक गए। रोहिणी के सभी 708 एलआईजी फ्लैट और नरेला में करीब 250 फ्लैट बुक हुए। रामगढ़ में 183 एलआइजी फ्लैट में से 153 फ्लैट बिक गए हैं।

10 सितंबर से शुरू हुई थी योजना के लिए बुकिंग

डीडीए अधिकारियों का कहना है कि 10 सितंबर से आवासीय योजना की बुकिंग शुरू हुई थी। द्वारका स्थित में सबसे अधिक मांग है। पेंटहाउस, सुपर एचआईजी, 18 एचआईजी और अधिकांश एमआईजी बुक हए गए हैं। यहां के 169 फ्लैटों के लिए लगभग दो हजार लोगों ने आवेदन किया था।

फिसली दलबदलूओं की जुबां,

हरियाणा में फिसली दलबदलूओं की जुबां,
अपने ही पार्टी का कर रहे काम तमाम।
ख़ुद की ही पार्टी को बता रहें है दमनकारी,
समझ नहीं आ रहा यह कैसी है कलाकारी।
पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ बयान दे रहे,
कार्यकर्ता सकते में है वह भी खफा हो रहे।
कांग्रेस नेताओं के बयान ज्यादा गड़बड़ा रहे,
वे तो अभी भाजपा की सरकार बनवा रहे।
एक ने तो पुरानी पार्टी के लिए वोट मांग लिए,
कार्यकर्ता बोला जीत के भी बुझा दिये दिए।
उम्मीदवार ने कांग्रेस को ही गैस पर घेर
दिया,
अरे, जीत रहा था वह खुद ही पानी फेर
दिया।
विपक्षी दल बयानों पर खूब तंज कस रहे हैं,
मतदाता वोट देने से पहले ही खूब हँस रहे हैं।
कौन गुप्ता, कौन बलवान? रंगा या मोहित!
पता नहीं किस-किसका कौन कर रहा
अहित?
अब तो न जाने क्या-क्या हो रहा है वायरल?
किसी की जीत और हार का बज रहा
सायरन।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986

राजधानी में रामलीला के लिए तैयारियां जोरों पर, झूलों और स्वादिष्ट व्यंजनों का ले सकेंगे आनंद

राजधानी दिल्ली के यमुनापार में रामलीला की धूम मची है। इस बार कई जगहों पर भव्य मंचन होगा। केदारनाथ मंदिर और हवा महल की प्रतिकृतियां इसमें आकर्षण का केंद्र होंगी। लोग झूलों और स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। 2 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर को रावण दहन के साथ इसका समापन होगा।

पूर्वी दिल्ली। यमुनापार की रामलीला समितियों ने प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी रामलीला मंचन के भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार यमुनापार में कई जगहों पर रामलीला का मंचन देखने को मिलेगा। सभी रामलीला समितियों की ओर से भूमि पूजन भी करा लिया गया है। सोनिया विहार, आइपी एक्सटेंशन, विवेक विहार, मयूर विहार फेज-तीन, शास्त्री पार्क, कैलाश नगर, गीता कालोनी, कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड व अन्य इलाकों में रामलीला मंचन का आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए टेंट, लाइटें, मंच, कलाकारों के लिए स्थान, झूले, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल व खरीदारी के लिए दुकानें बनने की तैयारियां जोरों पर हैं।

दो अक्टूबर से शुरू होने वाली रामलीला का समापन रावण दहन के साथ 12 अक्टूबर को किया जाएगा। इन दिनों में यमुनापार श्रीराम की भक्ति में डूबा नजर आएगा। समितियों के पदाधिकारियों ने बताया कि इतने वर्षों से रामलीला मंचन का उद्देश्य नई पीढ़ी को भगवान राम के आदर्शों से अवगत कराना है।

देखने को मिलेगी केदारनाथ मंदिर और हवा महल की प्रतिकृति

आईपी एक्सटेंशन में श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की ओर से मंचन किया जाएगा। इसमें लोगों को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भी देखने को मिलेगी। मंदिर की यह प्रतिकृति 50 फुट लंबी और 70 फुट चौड़ी होगी। वहीं कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में श्री बालाजी रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित होने वाली रामलीला मंचन के प्रवेश द्वार को हवा महल की प्रतिकृति के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह प्रतिकृति 60 फुट लंबी और 150 फुट चौड़ी होगी।

रामलीला के साथ उठा सकेंगे मेले का आनंद

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि रामलीला के आयोजन स्थल पर बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए झूलों की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टाल और खरीदारी के लिए कई आकर्षक दुकानों को भी तैयार किया जा रहा है, जिससे लोग रामलीला मंचन के साथ-साथ मेले का भी आनंद उठा सकेंगें।

चाक-चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि रामलीला मंचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा जाएगा। स्थानीय पुलिस को पहले ही लिखित में सूचना दी जा चुकी है। साथ ही प्रवेश व निकास द्वार और पूरे टेंट के अंदर जगह-जगह निजी बाउंसर भी तैनात किए जाएंगे। ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। पार्किंग में खड़े वाहनों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए जाएंगे।

नोएडा एयरपोर्ट के आसपास विभिन्न परियोजनाओं में आएगी तेजी, विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए नई समिति गठित

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने एक नई समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. अरुणवीर सिंह करेंगे। समिति में प्राधिकरण के दोनों अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) ओएसडी और महाप्रबंधक सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इस समिति के गठन से काम में तेजी आएगी।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में होने वाले निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए नई समिति गठित की गई है। यह समिति यमुना प्राधिकरण (यीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें प्राधिकरण के दोनों अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ), ओएसडी व महाप्रबंधक सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

समन्वय की कमी के कारण पहले गठित समिति को भंग कर दिया गया है। इस समिति में यमुना प्राधिकरण के अलावा नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी शामिल थे। समिति के गठन से एयरपोर्ट परिसर में विकास परियोजनाओं का काम तेजी से हो सकेगा।

एयरपोर्ट के अलावा कई इमारतों का होना है निर्माण

जेवर में 1334 हेक्टेयर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा होटल, कॉमर्शियल उपयोग की इमारतों का भी निर्माण होना है। इनके मानचित्र अन्य स्वीकृति के लिए पूर्व में समिति गठित की गई थी। इसमें यमुना प्राधिकरण के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था, नोएडा एयरपोर्ट के लिए शासन ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. का गठन किया है।

नागरिक उड्डयन विभाग के अलावा तीनों प्राधिकरण हिस्सेदार

इसमें नागरिक उड्डयन विभाग के अलावा तीनों प्राधिकरण हिस्सेदार हैं। इसलिए तीनों के अधिकारी समिति में शामिल किए गए थे। एयरपोर्ट यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है, इसलिए मानचित्र स्वीकृति के लिए उसकी शर्तों को पूरा करने की अनिवार्यता है।

एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके

लेकिन समिति के सदस्यों में समन्वय का जबरदस्त अभाव रहा। अधिकतर सदस्यों ने परियोजनाओं को स्वीकृति देने संबंधित फाइलों पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी की। यमुना प्राधिकरण सीईओ को शासन और बोर्ड से अनुमति लेकर इन फाइलों पर अपनी हस्ताक्षर से स्वीकृति देनी पड़ी। एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके।

इसे देखते हुए यमुना प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक में नई समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया और इसे स्वीकृत कर लिया गया। डा. अरुणवीर सिंह कहना है कि समिति के अध्यक्ष यमुना प्राधिकरण सीईओ होंगे। दोनों एसीईओ सदस्य, मुख्य विधिक सलाहकार, ओएसडी व महाप्रबंधक नियोजन भी समिति के सदस्य हैं। समिति लेआउट संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होगी।

ग्रेटर नोएडा की JP सोसाइटी में बिल्डर ने किया था अवैध कब्जा, लोगों ने किया ध्वस्त; प्राधिकरण ने दी चेतावनी

ग्रेटर नोएडा की जेपी सोसाइटी के निवासियों ने नेचर पार्क में बिल्डर द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने बिल्डर को चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की जाएगी। निवासियों ने अतिक्रमण की जांच के लिए कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। बिल्डर ने निवासियों की बिना सहमति के प्राधिकरण में कागज लगा दिए।

गुरुग्राम। ग्रेटर नोएडा। जेपी सोसायटी के निवासियों ने नेचर पार्क में बिल्डर की तरफ से की गई अतिक्रमण को जाकर ध्वस्त कर दिया। सूचना पर मुख्य कार्यपालक के निर्देश पर पहुंची प्राधिकरण की टीम ने बिल्डर को चेतावनी दी कि दोबारा किसी तरह का अतिक्रमण न करे।

जेपी सोसायटी स्थित नेचर पार्क में बिल्डर ने अतिक्रमण कर लिया था। इसको लेकर सोसायटी के निवासियों में आक्रोश व्याप्त था। शनिवार को जेपी सोसाइटी में स्टार कोर्ट अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पार्क पूरे ग्रेटर नोएडा का है। बिल्डर ने निवासियों की बिना सहमति के प्राधिकरण में कागज लगा दिए। इससे सभी आक्रोशित हो गए और कार्रवाई के तौर पर मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया।

प्राधिकरण की टीम ने बिल्डर को दी चेतावनी

सूचना पर पहुंची प्राधिकरण की टीम ने बिल्डर को चेतावनी दी है कि वह दोबारा यदि किसी तरह का अतिक्रमण करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। निवासियों ने अतिक्रमण की जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग करने का निर्णय लिया है। सभी ने एक स्वर में कहा कि सभी की जिम्मेदारी है कि पार्क को बचाया जाए।

खुशखबरी! इंदिरापुरम और नोएडा के बीच जल्द रफ्तार भरेगी मेट्रो, GDA को मिले आदेश

GDA News गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने जीडीए को आदेश दिया है कि इंदिरापुरम और नोएडा के बीच मेट्रो चलाया जाए। इसके लिए हर जरूरी संभव काम शुरू हो। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैटों की कई शिकायतें आ रही है। जिसे प्रशासन दूर करे। गर्ग ने वायु और जल प्रदूषण के साथ ही गंदगी को लेकर भी चिंता जताई है।

गाजियाबाद। कलक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद अतुल गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान जीडीए, नगर निगम, आवास विकास, विद्युत, कृषि, प्रदूषण, राजस्व, गंगा समिति, हरनंदी नदी आदि पर वार्ता की गई।

सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Aawas Yojana) के तहत जीडीए द्वारा आवंटित फ्लैटों में अनेक प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, जीडीए उपाध्यक्ष इसकी जांच कराएं और पात्र लाभार्थी को मिलने वाले सुविधाएं उन्हें दिलायें। उन्होंने ने जीडीए वीसी को इंदिरापुरम और नोएडा के बीच मेट्रो (Indirapuram to Noida Metro) चलाने का प्रस्ताव बनाने निर्देश दिया है।

उन्होंने वायु-जल प्रदूषण और गंदगी के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसके निस्तारण के बारे में जानकारी ली। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के लगभग 2.5 करोड़ के चालान किए गए हैं और कुछ फैक्ट्रियां सीज कर दी गई हैं।

मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जींस रंगाई की फैक्ट्रियों द्वारा केमिकल वाला गंदा पानी सीधे भूगर्भ में डाला जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि जल एवं भूगर्भ जल को दूषित करने वालों के खिलाफ टीम बनाकर अभियान चलाया जाएं और सख्त कार्रवाई की जाए।

महापौर ने बताया कि कूड़ा निस्तारण के लिए जल्द ही वेस्ट एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा है। लोनी विधायक ने बताया कि लोनी क्षेत्र में कुछ जगहों पर रात में तार जलाए जाते हैं जिसे रोकना आवश्यक है। बैठक में इसे रोकने व सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

हरनंदी की हो सफाई के लिए बने डीपीआर

कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि पूर्वांचल भवन, उत्तरांचल भवन सहित जनपद में बने अनेक ऐसे भवन हैं जो सरकार द्वारा बनवाए गए हैं लेकिन अभी तक उनकी देखरेख और संचालन का किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

हरनंदी को साफ-स्वच्छ बनाने बनाने की आवश्यकता है। इस पर सांसद अतुल गर्ग ने महापौर सुनीता दयाल को हरनंदी को स्वच्छ और उसके सुंदरीकरण के लिए डीपीआर बनवाने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग को सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को पूरा सहयोग करने के लिए कहा।

बैठक के दौरान महापौर ने सड़कों के किनारे बन रहीं झुग्गियां और बस्तियों में रहने वाले लोगों की जांच का मुद्दा भी उठाया। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एनएचआइ द्वारा बनाई गई सड़क का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा सड़क नाले से बहुत नीचे हैं।

इससे नाला ओवरफ्लो होने पर सड़क पर गंदा पानी भर जाता है। उन्होंने कहा कि एनएचआइ ने यह सड़क गलत तरीके से बनाई है। एनएचआइ इसे जल्द-जल्द ठीक कराए।

जर्जर तार और पानी की टंकियों की मरम्मत

लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर के जनप्रतिनिधियों ने गांवों में जर्जर तारों और पानी की टंकियों का मुद्दा उठाया। इस पर विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि जर्जर तारों को सही कराने का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि कहीं ज्यादा ही जर्जर तार है तो उसकी शिकायत दे दें। उसे तुरंत ठीक कराया जाएगा।

जल निगम के अधिकारी ने बताया कि पानी की टंकियों की मरम्मत व देखरेख का कार्य नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद का होता है वह कार्य उन्हें स्वयं करना है। बाकी जल से संबंधित कनेक्टीविटी का कार्य निरंतर चल रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि मोदीनगर और मुरादनगर क्षेत्र के 12 में से 09 गांवों में कार्य प्रगति पर है, जो कि जल्द पूरा करा दिया जाएगा।

लोनी विधायक ने लोनी के गांवों को भी आदर्श ग्राम में जोड़ने की बात कही। इस पर सांसद ने कहा कि आगामी योजनाओं में लोनी के भी गांवों को शामिल किया जाएगा। सभी जन प्रतिनिधियों ने साइबर क्राइम में पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज न होने का मुद्दा भी बैठक में उठाया।

इस दौरान बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान, जिला पंचायत अध्यक्ष डा. ममता त्यागी, मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी, मोदीनगर की विधायक डा. मंजू सिवाच भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह, जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स, सीडीओ अभिनव गोपाल आदि लोग मौजूद रहे।

हिंदुत्व में रुकावट हैं दलितों पर अत्याचार

योगेंद्र योगी

विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ग में अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण देने और क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने पर फैसला दिया तो सभी दलों और संगठनों ने जमकर शोर-शराबा किया। इसके विपरीत इन पर होने वाले अत्याचारों और विकास के मुद्दों पर राजनीतिक दलों का कोई सरोकार नहीं है। एक तरफ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ दलितों पर अत्याचारों के मामले बढ़ रहे हैं'

हिंदुओं की एकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का यह सपना शायद ही कभी पूरा हो सकेगा। देश में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचारों के मामले में देशभर में उत्तरप्रदेश पहले, मध्यप्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। सर्वाधिक आश्चर्य यह है कि हाशिए पर रह रहे इन वर्गों पर अत्याचारों का मामला राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन सका। इन वर्गों की दुहाई के लिए घडियाली आंसू बहाने वाले राजनीतिक दलों और संगठनों ने इन अत्याचारों पर धरना-प्रदर्शन करना तो दूर, मुंह तक नहीं खोला। भाजपाशासित राज्यों में एससी-एसटी पर अत्याचार शीर्ष पर होने के बावजूद यह मुद्दा चिंता का विषय नहीं बन सका। अत्याचारों के आंकड़ों की यह तस्वीर भाजपा के हिंदुओं के एकता प्रयासों की सच्चाई उजागर करती है। एक सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों (एससी) के खिलाफ 97.7 प्रतिशत अत्याचार 13 राज्यों में केंद्रित थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में 12287 मामले (23.78 प्रतिशत), राजस्थान में 8651 मामले (16.75 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश में 7732 मामले (14.97 प्रतिशत) दर्ज किए गए। इसके अलावा अन्य राज्यों में अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें बिहार में 6799 मामले (13.16 प्रतिशत), ओडिशा में 3576 मामले (6.93 प्रतिशत) और महाराष्ट्र में 2706 मामले (5.24 प्रतिशत) शामिल हैं। वर्ष 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए कुल मामलों में से लगभग 81 प्रतिशत केवल इन छह राज्यों में दर्ज किए गए। इस अधिनियम के तहत 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ कुल 51656 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ये मामले भारतीय दंड संहिता के तहत भी दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि एसटी के खिलाफ अत्याचार के अधिकांश मामले भी 13 राज्यों में हुए।

एसटी से जुड़े 9735 मामलों में से मध्य प्रदेश में 2979 मामले (30.61 प्रतिशत), राजस्थान में 2498 मामले (25.66 प्रतिशत) और ओडिशा में 773 मामले (7.94 प्रतिशत) दर्ज किए गए। एसटी से संबंधित अन्य मामलों में महाराष्ट्र में 691 मामले (7.10 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश में 499 मामले (5.13 प्रतिशत) शामिल हैं। इस रिपोर्ट में जांच और चार्जशीट से संबंधित डेटा भी प्रस्तुत किया गया है। अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों में 60.38 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए, जबकि झूठे दावों या सबूतों की कमी के कारण 14.78 प्रतिशत मामलों में अंतिम रिपोर्ट दी गई। वर्ष 2022 के अंत तक 17166 मामलों की जांच अभी भी लंबित थी। अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में 63.32 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए, जबकि 14.71 प्रतिशत मामलों में अंतिम रिपोर्ट दी गई। 2022 के अंत तक 2702 मामलों की जांच जारी थी। रिपोर्ट में एक प्रमुख चिंता अधिनियम के तहत दोषसिद्धि दर में गिरावट है। साल 2022 में यह दर 2020 के 39.2 प्रतिशत से घटकर 32.4 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट में इन मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों की अपर्याप्त संख्या पर भी चिंता व्यक्त की गई है। 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 जिलों ने विशेष अदालतें स्थापित की हैं ताकि मामलों की तेजी से सुनवाई हो सके। रिपोर्ट में ऐसे विशिष्ट जिलों की पहचान की गई है जहां अत्याचार की घटनाएं काफी अधिक हैं, लेकिन केवल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसे जिलों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में, जहां अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों की अधिक संख्या दर्ज की गई, वहां कोई अत्याचार-ग्रस्त जिला नहीं बताया गया। रिपोर्ट में जाति आधारित हिंसा को रोकने और कमजोर समुदायों के लिए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन जिलों में हस्तक्षेप करने का आह्वान किया गया है। अनुसूचित जाति-जनजाति पर अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए किए गए सरकारी उपाय दिखावटी साबित हुए हैं। यह समस्या सुरसा की तरह मुंह फाड़े चली आ रही है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में एससी/एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में एससी/एसटी अपराधों से निपटने के लिए विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन वर्गों पर अत्याचारों के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान लगते रहे हैं।

यदि पुलिस ईमानदारी से कार्रवाई करती तो अत्याचारों के इन आंकड़ों की नौबत नहीं आती। एससी-एसटी अधिनियम-1989 संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो एससी एवं एसटी समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का निषेध करने तथा उनके विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम इस निराशाजनक वास्तविकता को भी स्वीकार करता है कि अनेक उपाय करने के बावजूद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उच्च जातियों के हाथों विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 (भेदभाव का प्रतिषेध), 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है, जिसका दोहरा उद्देश्य इन कमजोर समुदायों के सदस्यों की सुरक्षा के साथ-साथ जाति आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है। संशोधित एससी/एसटी अधिनियम-2018 में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है और इन पर अत्याचार के मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। एससी-एटी के उत्थान के लिए बनी संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चार वर्षों में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संसद में एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

भाजपा की रमा देवी की अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने पाया कि ये रिपोर्टें, यद्यपि आयोग द्वारा अंतिम रूप दे दी गई थीं, केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास रोक दी गई थीं। अनुसूचित जाति-जनजाति के वोट बैंक के लिए सभी राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, लेकिन जब मुद्दा उनके न्याय और विकास का हो तो सभी दलों को काठ मार जाता है। गौरतलब है कि विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ग में अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण देने और क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने पर फैसला दिया तो सभी दलों और संगठनों ने जमकर शोर-शराबा किया। इसके विपरीत इन पर होने वाले अत्याचारों और विकास के मुद्दों पर राजनीतिक दलों का कोई सरोकार नहीं है। सर्वाधिक आश्चर्य यह है कि एक तरफ देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाशिए पर मौजूद इन वर्गों पर अत्याचारों के मामलों में इजाफा हो रहा है। सिर्फ आरक्षण देने से इन वर्गों की सामाजिक-आर्थिक हालत अन्य वर्गों की तुलना में बराबरी हासिल नहीं कर सकती। यह तभी संभव होगा जब इनके विकास के लिए बनाई योजनाओं को व्यावहारिक स्तर पर अमलीजामा पहनाया जाएगा।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

देहरादून में बनेंगे 9 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन, सर्वे के बाद डीएम सविन बंसल ने दी मंजूरी

परिवहन विशेष न्यूज

प्रदूषण और यातायात की भीड़ से निपटने के लिए देहरादून जिला प्रशासन जल्द ही शहर में नौ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। डीएम सविन बंसल ने मीडिया को बताया कि देहरादून नगर निगम ने एक सर्वेक्षण के बाद नौ ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थानों का चयन किया है।

देहरादून डीएम सविन बंसल ने बताया कि ₹परियोजना शून्य-निवेश मॉडल पर आधारित होगी। ब्लू-चिप कंपनियों को सरकारी जमीन का एक छोटा टुकड़ा प्रदान किया जाएगा, जो ईवी चार्जिंग स्टेशन का आवश्यक बुनियादी ढाँचा स्थापित करेंगे। राजस्व-साझाकरण मॉडल पर अभी फैसला होना बाकी है।₹ डीएम बंसल ने कहा कि परियोजना को शुरू होने में दो महीने वक्त लग सकता है लेकिन इस वित्तीय वर्ष के भीतर पूरी तरह से ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू होने की जिला प्रशासन पूरी कोशिशों में है।

देहरादून के भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे गांधी पार्क, रिस्पना पुल, घंटाघर और आईटी पार्क के आसपास के क्षेत्रों में नौ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जिला प्रशासन की योजना है। राजधानी देहरादून में दिन-दूने रात-चौगुने के हिसाब से बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने में इन नौ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन से काफी मदद मिलेगी। सहायक बुनियादी ढाँचा तैयार होने के बाद दूनवासियों को ईवी की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक स्टेशन पर एक साथ दो वाहन एक बार चार्ज होने में 45-50 मिनट का समय लेंगे। अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन के चार पहिया वाहन भी इन स्टेशनों का उपयोग कर सकेंगे।

टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में 9,000 करोड़ रुपये की परियोजना का किया शिलान्यास

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स ने शनिवार, 28 सितंबर को तमिलनाडु में 9,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके जरिए टाटा मोटर्स जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) के लिए नेक्स्ट जनरेशन के वाहनों का निर्माण और निर्यात करेगी।

तमिलनाडु के रानीपेट जिले के पनपक्कम में स्थित यह परियोजना भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगी। टाटा मोटर्स इस परियोजना के माध्यम से 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगी।

टाटा मोटर्स समूह इस ग्रीनफील्ड विनिर्माण केंद्र में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का इरादा है। इस परियोजना को 250,000 से अधिक वाहनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्पादन चरणबद्ध तरीके से होगा और 5-7 वर्षों में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि टाटा समूह राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, ₹हम वैश्विक स्तर की ऑटो निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स का रानीपेट के पनपक्कम में नवीनतम विनिर्माण परियोजना स्थापित करने के लिए स्वागत करते हैं।₹

इस विनिर्माण केंद्र में 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित होंगे।

इसके अलावा कंपनी ने कहा कि संयंत्र के संचालन के लिए 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि अब उनका इरादा यहां अत्याधुनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर एक उन्नत वाहन कंपनी बनाने का है।

चंद्रशेखरन ने कहा, ₹हमें पनपक्कम को अपनी नेक्स्ट जनरेशन की कारों और एसयूवी का केंद्र बनाने की खुशी है, इसमें इलेक्ट्रिक और लग्जरी वाहन शामिल हैं। तमिलनाडु प्रगतिशील नीतियों वाला एक अग्रणी औद्योगिक राज्य है और योग्य और प्रतिभाशाली कार्यबल के साथ एक स्थापित ऑटोमोटिव हब है।₹

इस वर्ष मई में टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जेएलआर ने कहा था कि वह रेंज रोवर स्पोर्ट के साथ-साथ फ्लैगशिप रेंज रोवर मॉडल की असेंबलिंग पहली बार भारत में शुरू करने की योजना बना रही है। इससे कीमतों में काफी कमी आएगी।

टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट में फिलहाल रेंज रोवर वेलार, रेंज रोवर इवोक, जगुआर एफ-पेस और डिस्कवरी स्पोर्ट मॉडल का निर्माण होता है।

नई बीएमडब्ल्यू X3 भारत में साल 2025 में होगी लॉन्च, डिजाइन से लेकर फीचर्स तक सबकुछ मिलेगा नया

परिवहन विशेष न्यूज

4th जनरेशन BMW X3 अगले साल 2025 में होने वाले भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश की जाएगी। इसे पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में लाया जाएगा। नई BMW X3 को नया डिजाइन दिया गया है इसके साथ ही इंटीरियर भी पूरी तरह से नया रहने वाला है। भारत में यह 68 लाख रुपए से 70 लाख रुपए के करीब लॉन्च हो सकती है।

नईदिल्ली। BMW अपनी नई कार भारत में लाने की तैयारी कर रही है, जो 4th जनरेशन की BMW X3 रहने वाली है। इसे कंपनी साल 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश करेगी। इसे भारत में X3 20d डीजल और X3 20 पेट्रोल के रूप में बेचा जाएगा। इसके पेट्रोल वर्जन को एक साल पहले बंद कर दिया गया था, जिसे फिर से भारत में लाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि यह किन फीचर्स से लैस रहने वाली है।

BMW X3: एक्सटीरियर

4th जनरेशन BMW X3 को नया डिजाइन दिया गया है। इसके आगे की तरफ होरिजेंटल और डाइग्लनल स्लैट्स के साथ एक बड़ी ग्रिल के साथ LED लाइट दी गई है। इसके दोनों तरफ LED हेडलैंप और दोनों तरफ़ LED डेटाइम रनिंग लाइट दी गई है। इसमें चोड़े व्हील्स आर्च और 4 व्हील साइज़ ऑप्शन दिया गया है। इसके पीछे का हिस्सा काफी स्पोर्टी दिखाई देता है। इसके अलावा छोटी विंडशील्ड और नई टेल लाइट्स दी गई हैं।

BMW X3: इंटीरियर

इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ-साथ एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है, जो 7 और 5 सीरीज में भी देखने के लिए मिलता है। इसमें AC वेंट, एक इंटरेक्शन बार और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। सेंटर कंसोल में गियर नॉब और कैमरा, वॉल्यूम, नेविगेशन और अन्य के लिए बटन दिए गए हैं। इसका स्टीयरिंग व्हील एकदम नया दिया गया है। इसका केबिन पूरी तरह से रीसाइकिल की गई अपहोल्स्ट्री और पैनोरमिक सनरूफ से लैस है।

BMW X3: पावरट्रेन

इसके इंजन की बात करें तो यह X3 20 पेट्रोल में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर इंजन के साथ आने वाली है। इसका पेट्रोल वाला इंजन 206 bhp और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं, डीजल वाला इंजन 197 bhp और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके दोनों इंजन को आठ-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

BMW X3: कीमत

इसकी कीमत की बात करें तो यह 68 लाख रुपए से 70 लाख रुपए के करीब एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च हो सकती है। इसका मुकाबला मर्सिडीज-बेंज GLC, ऑडी Q5 और वोल्वो XC60 से देखने के लिए मिलेगा।

नई कावासाकी वर्सेस 1100 यूरोप में हुई लॉन्च, नया इंजन से लेकर नए फीचर्स मिले

परिवहन विशेष न्यूज

नई कावासाकी वर्सेस 1100 को यूरोप में लॉन्च किया गया है। इस बाइक में कई बदलाव किए गए हैं। इसके इंजन को बढ़ाने से लेकर स्ट्रोक और नए फीचर्स भी दिए गए हैं। इस बाइक में यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। भारत में अगले साल 2025 में लॉन्च हो सकती है।

नई दिल्ली। Kawasaki अपनी नई बाइक लॉन्च की है, जिसका नाम Kawasaki Versys 1100 है। यह एक टूरिंग मोटरसाइकिल है। इसे यूरोप में लॉन्च किया गया है। इस माइल-मंचर में कई बदलाव किए गए हैं। जिसकी वजह से कई पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है।

New Kawasaki Versys 1100: इंजन

इसके इंजन को 1,043 cc बढ़ाकर 1,099 cc का कर दिया गया है। जिसका असर यह है अब यह इंजन 133 bhp की पावर और 112.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके इनलाइन-फोर मिल का बोर 77mm ही रखा गया है, लेकिन स्ट्रोक की लंबाई को 59mm कर दिया गया है। साथ ही यह फ्लाईव्हील, एयर बॉक्स के अंदर लंबे इनटेक फ़नल, संकरे इनटेक पोर्ट और कम वाल्व लिफ्ट के साथ नए कैमशाफ्ट भी दिया गया है।

New Kawasaki Versys 1100: वेरिएंट

इसे तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो बेस, एस और एसई है। इसके टॉप-स्पेक एसई ट्रिम में शोवा इलेक्ट्रॉनिक सेमी-एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है। इसके बाकी दो वेरिएंट में कम एडजस्टमेंट प्रावधानों के साथ मैनुअल सस्पेंशन दिया गया है। इसमें 260 मिमी रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है। इतना ही नहीं कावासाकी इस बाइक में यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

New Kawasaki Versys 1100: कीमत

कावासाकी वर्सेस 1000 की बिक्री भारत में बंद कर दिया गया है। जिसे देखते हुए उम्मीद है कि जल्द ही Versys 1100 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। वर्सेस 1000 की एक्स-शोरूम कीमत भारत में 13.91 लाख रुपये थी। नई Versys 1100 कीमत इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

इस ईवी कार से ऑफिस जाना मेट्रो किराए से हैं सस्ता

परिवहन विशेष न्यूज

कार खरीदना आजकल लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है। कुछ लोग रोजाना ऑफिस जाने के लिए कार खरीदते हैं, तो कुछ टूर के लिए कार खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसकी कार का माइलेज अच्छा हो। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद कार चलाना महंगा हो गया है। ऐसे में हर कोई ऐसी कार चाहता है जो न सिर्फ अच्छा माइलेज दे बल्कि उसके फीचर्स भी बेहतर हों।

इलेक्ट्रिक कारें इस समय सबसे अच्छा विकल्प हैं, क्योंकि इनकी रनिंग कॉस्ट कम है। ईवी ड्राइव द फ्यूचर आपको टाटा टियागो ईवी के बारे में बताने जा रहा हैं, जो ऑफिस जाने वालों के लिए एक बेहतरीन कार है। इसकी रनिंग कॉस्ट इतनी कम है कि मेट्रो का किराया भी महंगा लगेगा।

टाटा टियागो ईवी कार दो वेरिएंट में आती है। इसका बेस मॉडल फुल चार्ज पर 250 किलोमीटर की रेंज देता है, जबकि टॉप वेरिएंट में यह रेंज 315 किलोमीटर तक जाती है। टियागो ईवी के टॉप वेरिएंट में 24kWh की बैटरी है। अगर आप इसे महीने में 1500 किलोमीटर (औसतन 50 किलोमीटर रोजाना) चलाते हैं तो महीने का खर्च 2,145 रुपये आएगा। अगर आप इसे साल में 20,000 किलोमीटर चलाते हैं तो यह खर्च 28,000 रुपये होगा।

अगर हम टियागो ईवी की तुलना पेट्रोल से चलने वाली टियागो से करें तो टियागो पेट्रोल में 35 लीटर का फ्यूल टैंक है। इसका माइलेज 18.42 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो फुल टैंक पर करीब 645 किलोमीटर की रेंज देता है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर मान लें तो 3,500 रुपये खर्च करने होंगे, यानी एक किलोमीटर चलाने का खर्च करीब 5.42 रुपये है। अगर आप इसे महीने में 1500 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको फ्यूल पर 8,130 रुपये खर्च करने होंगे।

दोनों कारों की कीमत की तुलना करके आप समझ सकते हैं कि टियागो ईवी आपकी जेब पर कितनी हल्की पड़ेगी। यह इलेक्ट्रिक कार किसी भी पेट्रोल कार के मुकाबले सालाना करीब 80,000 रुपये बचा सकती है। अगर आप ऑफिस जाने के लिए ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिसकी रनिंग कॉस्ट कम हो तो टियागो ईवी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है।

नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का किया उद्घाटन

जामठा क्लोवर लीफ, जामठा, नागपुर। हरित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरित क्षेत्र स्थापित करने और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित और प्राकृतिक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के नागपुर-हैदराबाद सेक्शन पर नागपुर के जामठा क्लोवर लीफ में 14 करोड़ रुपए के निवेश से ऑक्सीजन बर्ड पार्क (अमृत महोत्सव पार्क) का शनिवार, 28 सितंबर को सांसद श्री श्यामकुमार बर्वे जी, विधायक श्री टेकचंद सावरकर जी, श्री आशीष जायसवाल जी, श्री विकास कुंभारे जी, श्री सुधाकर कोहले जी, सेक्रेटरी श्री अनुराग जैन जी और अधिकारियों की उपस्थिति में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया।

ऑक्सीजन बर्ड पार्क (अमृत महोत्सव पार्क) नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के किनारे जामथा के पास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित एक पर्यावरण-पहल है। सामाजिक वानिकी के लिए समर्पित 2.5 हेक्टेयर सहित कुल 8.23 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए, पार्क को प्राकृतिक पक्षी आवास और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजक स्थान के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्यावरणीय स्थिरता और मनोरंजक सुविधाओं को एकीकृत करने वाली इस परियोजना को औपचारिक रूप से मार्च 2023 में ₹14.31 करोड़ की विकास लागत के साथ मंजूरी दी गई थी।

इस पार्क का विचार केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा आरओ नागपुर को दिए गए सुझाव से आया था, जिसमें उन्होंने मध्य भारत के इस हिस्से में पाए जाने वाले पक्षियों की विविधता को देखने के साथ-साथ नागरिकों के मनोरंजन के लिए एनएचएआई भूमि पर अमृत महोत्सव पार्क विकसित करने का सुझाव दिया था। इस पार्क का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित और प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए एक हरित क्षेत्र की स्थापना करना था। प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की नकल करने के लिए डिज़ाइन किए गए वातावरण में स्थित, पार्क का उद्देश्य स्थानीय और प्रवासी पक्षी आबादी दोनों को संरक्षित करना है। इस पहल को नागपुर शहर के चारों ओर एक चार-लेन स्टैंडअलोन रिंग रोड विकसित करने की व्यापक अवसंरचना परियोजना में अतिरिक्त कार्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें पार्क जामथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास क्लोवर लीफ चौराहे पर स्थित है।

ऑक्सीजन बर्ड पार्क (अमृत महोत्सव पार्क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित एक पर्यावरण-पहल है। सामाजिक वानिकी के लिए समर्पित 2.5 हेक्टेयर सहित कुल 8.23 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए, इस पार्क को प्राकृतिक पक्षी आवास और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजक स्थान इन दोनों के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पार्क का उद्देश्य स्थानीय और प्रवासी पक्षी की प्रजातियों को संरक्षित करना है।

बर्ड पार्क में संरक्षण और पारिस्थितिकीय संवर्धन के उद्देश्य से कई अलग-अलग क्षेत्र होंगे। जिसमें दुर्लभ और लुप्तप्राय वृक्ष क्षेत्र, कमल-लिली पैड तालाब, पक्षियों के आवास के लिए रीड बेड, धूल और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बांबुसेटम, वायु की गुणवत्ता बढ़ाने और वन्यजीवों को आकर्षित करने के लिए वृक्षारोपण क्षेत्र, पक्षियों के घोंसले के लिए ताड़ का पौधारोपण क्षेत्र का समावेश है। साथ ही पक्षियों को आकर्षित करने के लिए पार्क की वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के पेड़, नरकट, जलीय पौधे और झाड़ियाँ शामिल हैं जिन्हें विशेष रूप से जैव विविधता को बढ़ाने के लिए चुना गया है। उल्लेखनीय प्रजातियों में नीम, भारतीय मूंगा वृक्ष, जल लिली, कमल, चमेली और करोंदा शामिल हैं।

वानिकी, वन्य जीवन और पशुपालन में नौकरी के अवसर और कैरियर

विजय गर्ग

जैसे-जैसे पृथ्वी पर और विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में जनसंख्या बढ़ रही है, ढांचागत विकास के लिए अधिक खाद्यान्न और लकड़ी के लिए कृषि भूमि की मांग बढ़ रही है, जिससे जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। हालाँकि, खाद्यान्न और लकड़ी दोनों ही मानव जाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें केवल वन भूमि की कीमत पर ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कृषि भूमि और वन भूमि के बीच संतुलन समय की मांग है क्योंकि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मानव जाति के लिए और मानव जीवन के निरंतर विकास के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि वन किसी देश के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का हिस्सा होते हैं। प्राचीन काल से ही वन संसाधन मानव जीविका का स्रोत रहे हैं। वे सबसे अद्भुत जड़ी-बूटियों, औषधीय यौगिकों, प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधनों और सबसे बढ़कर वन्य जीवन का घर हैं। वानिकी और वन्य जीवन एक साथ चलते हैं क्योंकि वन वन्यजीवों के लिए घर के रूप में काम करते हैं जो पृथ्वी पर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वन संसाधन और संपदा भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों को वन आवरण, वन संपदा और संसाधनों को पुनर्जीवित करके कृषि और वन भूमि के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिससे इस क्षेत्र में युवा पीढ़ी के लिए करियर विकल्प खुलते हैं। इन करियर विकल्पों में वानिकी विशेषज्ञ, वानिकी प्रबंधन विशेषज्ञ और वन अधिकारी, वनपाल, डेंड्रोलॉजिस्ट, नृवंशविज्ञानी, कीटविज्ञानी, सिल्विकल्चरिस्ट (वन प्रसार और संस्कृति), वन रेंज अधिकारी, चिड़ियाघर क्यूरेटर आदि की सेवाएं शामिल हैं। वानिकी में लकड़ी की आपूर्ति में योगदान सुनिश्चित करने के लिए जंगलों और पेड़ों की विविधता की सुरक्षा शामिल है। वनपाल वन संसाधनों को आग, कीट, बीमारी, अतिक्रमण और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से बचाकर उनकी देखभाल करता है। वे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र के आधार पर कार्यालयों, प्रयोगशालाओं या बाहर काम कर सकते हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तरह वनों के दुरुपयोग के कारण भूस्खलन, बाढ़ और सूखे जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाएँ पैदा हुई हैं। जंगली जानवरों की अंधाधुंध हत्या के कारण कई दुर्लभ प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे हानिकारक प्रभावों, जंगलों के तेजी से कटने और वन्यजीवों में खतरनाक दर से कमी के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, विभिन्न सरकारें और विश्व निकाय और दुनिया भर के गैर सरकारी संगठन विश्व वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती पर जोर दिया गया है, जिससे इस दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक युवा उम्मीदवारों के लिए रोजगार के विभिन्न अवसर पैदा होंगे। उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करने के अवसर हैं वन संसाधनों के संरक्षण में रुचि रखने वाले सरकारी, अर्ध-सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन कॉरपोरेट के पास लकड़ी के लिए अपने स्वयं के बागान हैं वन संसाधनों का उपयोग करने वाले उद्योग औद्योगिक और कृषि सलाहकारों और परामर्शदाताओं को नियुक्त करते हैं भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) और इसके संबद्ध वानिकी अनुसंधान संस्थान जैसे वन अनुसंधान संस्थान और सामाजिक वानिकी और पर्यावरण-पुनर्वास संस्थान क्रमशः देहरादून और इलाहाबाद में स्थित हैं। वन्यजीव अनुसंधान संस्थान। प्राणी उद्यान वन्यजीव पर्वतमाला जोश से भरे युवा उत्साहीएडवेंचर के लिए ऊपर दिए गए किसी भी संगठन से जुड़कर देश के जंगलों की सुरक्षा का दायित्व ले सकते हैं। यह कार्यक्षेत्र न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी युवाओं को ढेर सारी नौकरियों का वादा करता है। इस क्षेत्र में कुछ करियर जिन्हें कोई भी चुन सकता है वे हैं:- वनपाल

: वनों की सुरक्षा और पुनर्जनन, वन्यजीव आवासों की रक्षा, जंगली आग की जाँच और उससे लड़ने, भूदृश्य प्रबंधन, इत्यादि के लिए जिम्मेदार। अनुभव के साथ वनवासी जनसंपर्क प्रबंधन, रिपोर्ट तैयार करने और बजट प्रबंधन में स्नातक हो सकते हैं। डेंड्रोलॉजिस्टः ये पेशेवर पेड़ों और लकड़ी के पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन में विशेषज्ञ हैं। उनके काम में इतिहास और जीवन काल पर शोध, पेड़ों की किस्मों को मापना, ग्रेडिंग करना, वर्गीकृत करना और वनीकरण के माध्यम से पेड़ों के सुधार के तरीकों और साधनों का अध्ययन करना आदि शामिल हैं। नृवंशविज्ञानीः अपने प्राकृतिक वातावरण में जानवरों के व्यवहार के विशेषज्ञ। नृवंशविज्ञानी किसी जीव के प्राकृतिक वातावरण में उसके विकास, व्यवहार, जैविक कार्यों आदि का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। नृवंशविज्ञानी चिड़ियाघरों, एक्वैरियम और प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए स्वस्थ आवास डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मानव शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए जानवरों के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। कीटविज्ञानीः कीटविज्ञानी विभिन्न प्रकार के कीड़ों और कीटों से होने वाली बीमारियों के अध्ययन और नियंत्रण में विशेषज्ञ हैं। सिल्वीकल्चरिस्टः यह पेशेवर समय-समय पर फसल देने वाले वृक्षारोपण के विकास में उपयुक्त है। वन रेंज अधिकारीः वन रेंज अधिकारी सार्वजनिक वनों, अभयारण्यों, वनस्पति उद्यानों आदि की देखभाल करते हैं। उनके साथ संरक्षक, लकड़हारा और अन्य कनिष्ठ कर्मी काम करते हैं। इस पद पर प्रवेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आईएफएस परीक्षा के माध्यम से होता है। चिड़ियाघर क्यूरेटरः वे चिड़ियाघरों में पशु कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं और संरक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं। चिड़ियाघर क्यूरेटर चिड़ियाघर के कार्यों और बंदी प्रजनन कार्यक्रमों के प्रशासन में भूमिका निभाता है। वे चिड़ियाघर संचालकों द्वारा बनाई गई रिपोर्टों की समीक्षा करते हैं, चिड़ियाघर के लिए बजटीय आवश्यकताओं की गणना करते हैं और अनुसंधान गतिविधि को प्रोत्साहित करते हैं। ऊपर उल्लिखित विभिन्न करियर विकल्पों के अलावा वानिकी विशेषज्ञों में बाहरी गतिविधियों को पसंद करना, रोमांच की भावना, अच्छा स्वास्थ्य, सहनशक्ति, शारीरिक फिटनेस, धैर्य, वैज्ञानिक स्वभाव, आयोजन क्षमता, जनसंपर्क कौशल, व्यावहारिकता, साहस, निर्णय लेने की क्षमता जैसी विशेषताएं हैं। लंबे समय तक काम करने की क्षमता, प्राकृतिक पर्यावरण और आवास के संरक्षण में वास्तविक रुचि, अनुसंधान और मन की शैक्षणिक प्रवृत्ति, जिज्ञासा, अवलोकन के उत्कृष्ट कौशल, कृषि और भूगोल में रुचि और संबंधित क्षेत्रों में उचित योग्यता हो सकती है। प्रतिष्ठित संगठनों के लिए वन्यजीव सलाहकार के रूप में विदेश में नौकरियां प्राप्त करें। विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) एक ऐसा संगठन है जो विशेष उल्लेख के योग्य है। कई संगठन कंपूचिया, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में काम के लिए इस क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों की भर्ती भी कर रहे हैं। जहां तक पशुपालन का सवाल है, पशुधन, डेयरी और पोल्ट्री-आधारित उद्योग के व्यावसायीकरण ने उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल की मांग में वृद्धि की है, जिससे पशुपालन और इसके संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक पेशेवर दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस पेशेवर दृष्टिकोण ने इस क्षेत्र में विभिन्न करियर विकल्पों के द्वार खोल दिए हैं। 'सेलेक्टियो' द्वारा पशु नस्ल सुधार जैसे विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रप्रजनन और कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पशु अनुसंधान, पोल्ट्री प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल, पशुधन बीमा और ग्रामीण विकास आदि के लिए संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। ये विशेषज्ञ पशुधन और घरेलू पशु धन के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में शामिल पेशेवर वांछनीय विशेषताओं के प्रजनन के लिए काम करते हैं, जैसे ताकत, परिपक्वता दर, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मांस की गुणवत्ता में सुधार; मवेशी, बकरी, घोड़े, भेड़, सूअर, मुर्गी, कुत्ते, बिल्ली या पालतू पक्षियों सहित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जानवरों में, और आनुवंशिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, जानवरों की आबादी की आनुवंशिक संरचना और लक्षणों की आनुवंशिकता का निर्धारण करते हैं। वे वांछनीय विशेषताओं के नए संयोजन प्राप्त करने के लिए मौजूदा उपभेदों या क्रॉस उपभेदों के भीतर जानवरों को क्रॉसब्रीड करते हैं, माता-पिता दोनों के वांछित उपभेदों वाली संतान का चयन करते हैं और स्वीकार्य परिणाम प्राप्त होने तक प्रक्रिया जारी रखते हैं। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और इस क्षेत्र के व्यावसायीकरण के साथ, पशुपालन के क्षेत्र में उपयुक्त पेशेवरों की भारी मांग है। हालाँकि कई मौजूदा फार्म पेशेवरों को अधिक अनुभवी पशुपालन पेशेवरों द्वारा काम पर प्रशिक्षित किया गया था और उन्होंने अपना पूरा जीवन खेतों पर बिताया है, फिर भी वर्तमान युवाओं को अपना काम अधिक दक्षता और अधिक कुशलता से करने के लिए फार्म प्रबंधन या अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। पेशेवर ढंग. इस क्षेत्र में काम करना उन उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद और प्रेरणादायक करियर विकल्प हो सकता है जो वास्तव में इस विशेष क्षेत्र में रुचि रखते हैं। हालाँकि यह शारीरिक रूप से कठिन और कभी-कभी गंदा होता है, फिर भी प्रकृति और पशुधन के करीब होने के कारण यह बहुत संतोषजनक नौकरियों में से एक है। कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार क्षेत्र से संबंधित किसी भी नौकरी में या क्षेत्र में एक उद्यमी के रूप में अच्छी कमाई कर सकते हैं।

नदी का जीवन

विजय गर्ग

हाल ही में खबर आई कि चेन्नई देश का प्रथम शहर हो गया है जहां भूमिगत जल बिल्कुल खत्म हो गया है। पानी के घटते स्रोत ने हमारे द्वारा किए गए अंधाधुंध विकास पर जो अट्टहास किया, उससे हम सभी एकबारगी सूख गए हैं। एक समय था जब गांव-गांव पानी के सोते बारह महीने बहते रहते थे। नदियां बहती रहती थीं, लेकिन अब स्थिति विपरीत है। बारिश रुकी नहीं कि सोते, नदियां भी अपनी कलकल बंद कर देते हैं। नदी क्षेत्र देश का छब्बीस फीसद भूभाग है और लगभग तैंतालीस फीसद आबादी इससे जुड़ी है। एक शोध के मुताबिक, पानी में आक्सीजन की मात्रा गिरने से नदी के भीतर चल रहा पारिस्थितिकी तंत्र मरने लगता है। एक हद के बाद वैज्ञानिक भाषा में नदी को मृत घोषित कर दिया जाता है। एक बार कोई नदी मर जाए, तो उसे फिर स्वस्थ करने में कम से कम तीस से चालीस वर्ष का वक्त लगता है। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण की वजह से यूरोप की कई नदियां यह हाल देख चुकी है। कुछ नदियों में तो आज तक जीवन पूरी तरह नहीं लौट सका है।

भारत की नदियां मुख्य रूप से वर्षा जल से पोषित होती हैं। फिर वे साल भर, यहां तक कि सूखे मौसमों में भी कैसे बहती हैं? जवाब है, वनों के कारण। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी बारहमासी नदियां बहती रहें, इसमें पेड़ों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। नदियां जीवनदायिनी हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति नदियों के समीप ही विकसित हुई थी। देश के सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार ये नदियां ही हैं। मगर विचित्र है कि देश में 521 नदियों के पानी की निगरानी करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की 198 नदियां ही स्वच्छ हैं। इनमें अधिकांश छोटी नदियां हैं। देश की बड़ी-बड़ी नदियां किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं, लेकिन उनको जल की आपूर्ति करने वाली करीब चार हजार पांच सौ से अधिक छोटी-छोटी नदियां सूख कर विलुप्त हो गई हैं। डब्लूआरआइ के मुताबिक, जल संकट के मामले में भारत विश्व में तेरहवें स्थान पर है। भारत के लिए इस मोर्चे पर चुनौती बड़ी है, क्योंकि

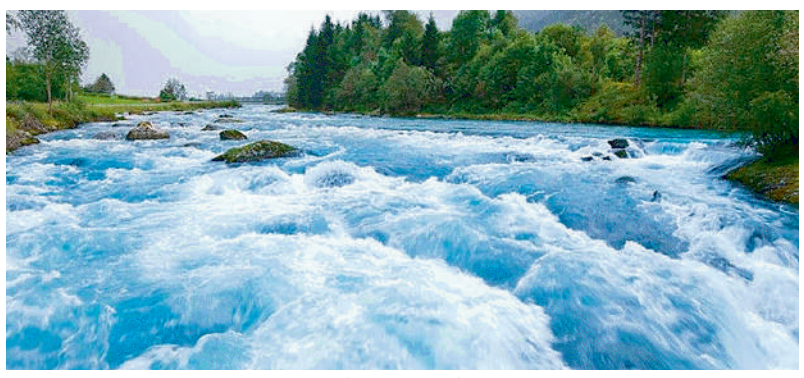

उसकी आबादी जल संकट का सामना कर रहे अन्य समस्याग्रस्त 16 देशों से तीन गुना ज्यादा है।

नदी की परिभाषा कहती है कि 'हिम, भूजल स्रोत और वर्षा के जल को उद्गम से संगम तक स्वयं प्रवाहित रखती हुई जो अविरलता निर्मलता और स्वतंत्रता से बहती हैं और सदियों से सूरज, वायु और धरती का आजादी से स्पर्श करती हुई जीव- सृष्टि से परस्पर पूरक और पोषक नाता जोड़कर जो प्रवाहित है, वह नदी है।' देश की सत्तर फीसद नदियां प्रदूषित हैं और मरने के कगार पर हैं। इनमें गुजरात की अमलाखेड़ी, साबरमती और खारी, आंध्र प्रदेश की मुंसी, दिल्ली में यमुना, महाराष्ट्र की भीमा, हरियाणा की मारकंडा, उत्तर प्रदेश की काली और हिंडन नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब भी बदहाल स्थिति में हैं।

इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। न्यूजीलैंड की संसद ने वहां की तीसरी सबसे बड़ी नदी वांगानुई को एक व्यक्ति की तरह अधिकार दिए। यह कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड ही नहीं, भारत के आदिवासी भी अपने आसपास की नदियों को अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी पूजा, आराधना करते हैं। इसके बाद दुनिया के अलग-अलग हिस्सों, जैसे कि कोलंबिया, आस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह में भी ऐसे ही कानून बनाए गए थे।

अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग चार हजार अरब घन मीटर पानी वर्षा के जल के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन उसका लगभग आठ फीसद पानी ही हम संरक्षित कर पाते हैं। शेष पानी नदियों और नालों के माध्यम से बह कर समुद्र में चला जाता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में वर्षा के जल को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके चलते जगह- जगह पोखर, तालाब, बावड़ी और कुआं आदि निर्मित कराए जाते। उनमें वर्षा का जल एकत्र होता था और वह वर्ष भर जीव-जंतुओं सहित मनुष्यों के लिए भी उपलब्ध होता था। आज स्थितियां विकट होती जा रही हैं, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान और कहीं है। अधिकांश राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में नदी बहुत कम दिखाई देती है और यह हमारी राजनीतिक चेतना के अभाव का सूचक है।

देश की सबसे पवित्र कहलाने वाली गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जब यात्रा के लिए चलते थे तो पीने के लिए गंगाजल लेकर चलते थे जो इंग्लैंड पहुंच कर भी खराब नहीं होता था। ब्रिटिश सेना भी युद्ध के समय गंगाजल अपने साथ रखती थी, जिससे घायल सिपाही के घाव को धोया जाता था। इससे घाव में संक्रमण नहीं होता था। ज्ञान की परंपरा में गंगा नदी सर्वोच्च थी। मानवीय रोगाणुओं को गंगाजल में नष्ट करने की क्षमता थी, जिससे सत्रह तरह के रोगाणु नष्ट हो जाते थे। आज हालात ऐसे हैं कि गंगा का पानी कई जगह पीने योग्य नहीं है। हमें अपनी भावनाओं के साथ कर्मों को भी धरातल पर रखकर विकास को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। सनद रहे कि नदियां हमारा भविष्य तय करने वाली हैं।

हिमालय का दर्द और सोनम वांगचुक की यात्रा

कुलभूषण उपमन्यु

हिमालय बचा रहेगा तो पूरा देश बचा रहेगा। हिमालय के लोगों की विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें वैकल्पिक विकास मॉडल पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए स्थानीय समाजों की समझ का उपयोग करना जरूरी है, जिसके लिए लद्दाख के लोगों की चुनी हुई सरकार की मांग तर्कसम्मत है, जिसे माना जाना चाहिए। इसी दृष्टि से लद्दाख को छठी अनुसूची में डालने की मांग है। इस अनुसूची में डाले जाने से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में स्थानीय समाजों की भूमिका सशक्त होगी और सरकार को भी संसाधनों के तर्कपूर्ण दोहन के लिए व्यवस्था बनाने में आसानी होगी

चौबीस दिन पैदल चलते हुए भाई सोनम वांगचुक हाल ही में नालागढ़ पहुंचे, जहां उनका स्थानीय साथियों ने भावपूर्ण स्वागत किया। लद्दाख से लेकर जगह-जगह उनकी यात्रा का इसी तरह स्वागत हो रहा है। सोनम जी के नेतृत्व में 100 के लगभग यात्री टोली हिमालय के दर्द को बांटते हुए हिमालय के संरक्षण का संदेश लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन दिल्ली पहुंचेंगे। अनादिकाल से पदयात्रा भारतवर्ष में शुद्ध जनहित और आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने और समाज को जगाने का सशक्त माध्यम रहा है। वांगचुक जी की यात्रा को मिलता समर्थन यह सिद्ध कर रहा है कि पदयात्रा आज भी शुद्ध जनहित और आध्यात्मिक संदेश फैलाने का सशक्त माध्यम है, जिसकी प्रासंगिकता असंदिग्ध है, बशर्ते यात्रा का लक्ष्य स्वार्थ-जनित नहीं होना चाहिए। एक बार मैं और मेरे साथी रतन चंद और रघुवीर सिंह पिरता हिमाचल और गढ़वाल की हिमालय बचाओ संपर्क वाहन यात्रा पर रेणुका जी पहुंचे। वहां हम एक साधू आश्रम में ठहरे। रात में भोजन के उपरांत आश्रम प्रमुख से अपनी यात्रा का आशय बताया तो वह कहने लगे, 'अरे, हिमालय तुम्हें बचा रहा है, तुम हिमालय को बचाने वाले कौन होते हो?'

फिर चर्चा शुरू हुई कि हिमालय की हमें बचाने की शक्ति हमारी गलत विकास की गतिविधियों के कारण और हमारे लालच के कारण अति दोहन के चलते नष्ट हो रही है। अतः हिमालय को बचाने का अर्थ है हिमालय की वायु को शुद्ध करने की शक्ति, जल संरक्षण की शक्ति, जलवायु नियंत्रण की शक्ति, जैव विविधता द्वारा देश की सेवा करने की शक्ति, थके हारे मानस को शांति प्रदान करने की शक्ति, सदानीरा नदी तन्त्र द्वारा सेवा करने की शक्ति को लालच के लिए नुकसान पहुंचाने से बचाना और नुकसान पहुंचाने वालों को रोकना ही हिमालय को बचाना है। बस इतना सुनते ही आश्रम प्रमुख गदगद हो गए और अपना पैड निकाल कर अपना संदेश भी लिख दिया और इसको भी जगह जगह दिखाने का हमें आदेश दिया। हिमालय के जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक अवदान हैं, उनको बचाना। हिमालय सांस्कृतिक विविधता का भी भंडार है। किसी भी समाज के दीर्घकालिक हित के लिए सांस्कृतिक विविधता भी बहुत आवश्यक तत्व है। हिमालय में यदि बर्फ न रहे तो हिमालय का क्या अर्थ रह जाएगा? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में वहां के समाजों का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य समाज और प्रकृति तन्त्र का संतुलित रिश्ता ही पारिस्थितिकीय संतुलन का आधार है। हमारे आज के विकास का मॉडल इस तत्व की अनदेखी कर रहा है। हम सोचने लगे हैं कि सभी समस्याओं के समाधान इंजीनियरिंग और तकनीकी समझ से मिल सकते हैं। किन्तु ऐसा है नहीं। हम पानी का एक कतरा, हवा का एक श्वास, मिट्टी का एक ढेला, प्रकृति के तत्वों का प्रयोग किए बिना, बना नहीं सकते। जिन्दा रहने के लिए हवा, पानी और भोजन ही सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। हमारा विकास इन्हीं पर आघात कर रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे नदियों के अस्तित्व पर खतरा आ गया है। वे मौसमी होकर रह जाएंगी। मिट्टी हमारी रासायनिक खेती पद्धति द्वारा जहरीली होती जा रही है। वही जहर हमारे खाद्य पदार्थों में पहुंच रहे हैं। हवा को सभ्यता का धुआं जहरीला कर रहा है, तो संकट जिन्दा रहने पर आने वाला है।

हिमालय क्योंकि सबसे संवेदनशील परिस्थिति तन्त्र है, इसलिए यहां होने वाले दुष्प्रभाव अधिक घातक होंगे और पूरे देश को प्रभावित करेंगे। लोग अब इन मुद्दों को समझने लगे हैं, इसीलिए लद्दाख की आवाज को हिमाचल में इतना समर्थन मिल रहा है। असल में यह आवाज पूरे हिमालय की है। मुख्यधारा के विकास मॉडल से यहां जो परिस्थितितंत्र को नुक्सान हो रहा है, उसकी और अधिक अनदेखी पूरे देश के लिए घातक सिद्ध होगी। हिमालय बचा रहेगा तो पूरा देश बचा रहेगा। हिमालय के लोगों की विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें वैकल्पिक विकास मॉडल पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए स्थानीय समाजों की समझ का उपयोग करना जरूरी है, जिसके लिए लद्दाख के लोगों की चुनी हुई सरकार की मांग तर्कसम्मत है, जिसे माना जाना चाहिए। इसी दृष्टि से लद्दाख को छठी अनुसूची में डालने की मांग है। इस अनुसूची में डाले जाने से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में स्थानीय समाजों की भूमिका सशक्त होगी। और सरकार को भी संसाधनों के तर्कपूर्ण दोहन के लिए व्यवस्था बनाने में आसानी होगी। कई दशकों से हिमालय में वैकल्पिक विकास मॉडल अपनाने की मांग हो रही है। योजना आयोग के समय से ही यह मुद्दा उठता रहा है। किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला है।

लोगों को छिटपुट संघर्षों के कारण कहीं अपनी बात मनवाने में सफलता मिली है। किन्तु असली समाधान तो वैज्ञानिक समझ से हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी के अनुरूप विकास मॉडल लागू करने से ही होगा। इसके लिए पांचवीं और छठी अनुसूची कुछ संरक्षण तो दे ही सकेंगे। तो क्यों न ट्रांस हिमालय को छठी अनुसूची और शेष हिमालय को पांचवीं अनुसूची में डाल कर हिमालय को मुख्य धारा विकास की विनाशकारी दौड़ से बचाया जाए। जो मैदानी इलाकों के लिए ठीक है, वह हिमालय के लिए भी ठीक हो, यह जरूरी नहीं। यह काम वैज्ञानिक समझ से हल किया जाए। इसमें दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं दिया जा सकता।

मानव मन की गहराइयों की खोज

विजय गर्ग

जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तुलना मानव संज्ञान से की जाती है, मन का रहस्य और अधिक जटिल होता जाता है, जिससे इसकी अप्रयुक्त क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। मानव मस्तिष्क एक अद्वितीय जैविक इकाई है जिसकी पहुंच की लंबाई और दृष्टि की सीमा को अभी भी पूरी तरह से मैप किया जाना बाकी है। कई लोगों का मानना है कि एक औसत दिमाग अपनी क्षमता के 30 प्रतिशत से भी कम पर काम करता है। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में रखें तो मामला और भी जटिल हो जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक सिद्धांत चल रहा है जो बताता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संस्थाओं में मानव मस्तिष्क की तरह ही जैविक कार्य करने की क्षमता होती है। इसके साक्ष्य काफी मिश्रित हैं। समय के साथ कुछ निष्कर्ष सामने आ सकते हैं। हालाँकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में जैविक विकास और वृद्धि के लिए इसकी संभावनाएँ और क्षमताएँ शामिल हैं। जैसा कि देखा गया है, देर-सबेर उत्तर सामने आ ही जायेंगे। अन्यथा भी, मानव मस्तिष्क अपने अस्तित्व का स्वतः संज्ञान वाला तर्क है। इसका मानचित्रण करने का प्रयास वास्तव में मानव प्रयास के रोमांचक पहलुओं में से एक है। मस्तिष्क के मानचित्रण में कुछ सफलताओं के बावजूद, मस्तिष्क के कार्य के ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर शारीरिक और परिचालन दोनों रूप से करीब से नज़र डालने की आवश्यकता है। दिलचस्प बात यह है कि इन सबके बावजूद, मनुष्य के 'दूसरे बचपन' का एक सामान्य संदर्भ है, जहां लोग एक निश्चित उम्र तक पहुंचने पर बच्चों जैसे लक्षणों के साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार, जूरी ने यह भी तय कर दिया है कि मस्तिष्क का मूल अभिविन्यास किस उम्र तक पूरी तरह से विकसित हो जाता है। किसी को यह भी जानना होगा कि 'चेतन' मस्तिष्क और 'अवचेतन' मस्तिष्क के बीच संबंध विकसित करने के लिए यह कब परिपक्व होता है। उपरोक्त आख्यान की विविध व्याख्याओं के बावजूद, यह स्पष्ट है कि किसी न किसी स्तर पर मन की बुनियादी नींव ठोस प्रतीत होती है। ऐसा ही एक उदाहरण बढ़ते इंसान पर बचपन के शुरुआती अनुभवों का प्रभाव है। बचपन के प्रारंभिक वयस्कता में उभरने के चरण होते हैं। यह सब व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के तरीकों का अभिन्न अंग बन जाता है। लोकप्रिय रूप से, यह वित्त, लिंग या यहां तक कि मूल्यों के मामलों पर बढ़ते व्यक्ति के रुझान को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। सूची को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस बिंदु तक और अधिक, जो एक क्रियाशील रूप से वयस्क मानव मस्तिष्क के निर्माण में लगने वाले सभी प्रभावों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं जानता है। बहुत बार, मानव मस्तिष्क पर ऐसे अव्यक्त प्रभाव हो सकते हैं जो वयस्कता के बहुत बाद तक प्रकट नहीं हो सकते हैं। कुल मिलाकर, कई अस्पष्टताएँ बनी हुई हैं, और इसलिए कई विरोधाभास भी हैं जो मन की कार्यप्रणाली के संबंध में जीवित रहते हैं। सबसे बढ़कर, आमतौर पर यह माना जाता है कि हार्मोनल परिवर्तन दिमाग के कामकाज को प्रभावित करते हैं। कथित तौर पर पुरुष और महिला दोनों अपने बाद के जीवन में रजोनिवृत्ति से गुजरते हैं। कई लोगों का मानना है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रजोनिवृत्ति के प्रभाव अधिक पहचाने जा सकते हैं। हालाँकि, एक मुद्दे का पूरी तरह से उत्तर दिया जाना बाकी है: वे कौन से कारक हैं जो मन के कामकाज को प्रभावित करते हैं? व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक अन्य तत्व मानसिक आघात से उत्पन्न परिणाम है। इसमें व्यक्ति की विचार प्रक्रिया को पटरी से उतारने और वास्तव में कई मूल्यों को प्रभावित करने के कई अनुमान हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो विचार, चिंतन, विश्लेषण और अनुसंधान के कई क्षेत्रों में मन की गतिशीलता को समझने के संकेत हो सकते हैं। यह एक हो सकता हैचुनौती, लेकिन ऐसी चुनौती जिससे बचा नहीं जा सकता। इसके अलावा, इसके कुछ ट्रांसजेनरेशनल पहलू भी हैं। मान लीजिए, दो माता-पिता एक-दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, या अकेले और सामूहिक रूप से एक बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, यह बच्चे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। यह पीढ़ियों तक जारी रह सकता है। शारीरिक रूप से, कुछ जीनों का स्थानांतरण पीढ़ियों के बीच होता हुआ जाना जाता है। यह न केवल शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में है, बल्कि कुछ बीमारियाँ भी हैं जो किसी पीढ़ी में दादा-दादी में से किसी एक को प्रभावित कर सकती हैं और दो पीढ़ियों बाद वंशज की शारीरिक प्रणाली में फिर से उभर सकती हैं। आज की स्थिति के अनुसार, इस प्रक्रिया की मैपिंग के लिए बहुत अधिक अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें मानव शरीर विज्ञान, शारीरिक मानव विज्ञान, औषधियों और अन्य का संपूर्ण शोध एजेंडा भी शामिल है। इस तरह का विषय न केवल मानवविज्ञान, मनोविज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान और अधिक के एकीकृत दृष्टिकोण का हकदार होगा, बल्कि उचित अंतःविषय ढांचे के साथ समर्थन विषयों की एक पूरी व्यवस्था का भी हकदार होगा। इससे मनुष्य के शरीर विज्ञान और मस्तिष्क तथा दिमाग की संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह ऐसा कार्य है जिसे टाला नहीं जा सकता।

छुट्टी वाले दिन खुला है मार्केट, BSE नहीं NSE पर होगा ट्रेडिंग सेशन

परिवहन विशेष न्यूज

शेयर बाजार का साप्ताहिक अवकाश शनिवार रविवार होता है। इसके अलावा फेस्टिवल वाले दिन भी बाजार बंद रहता है। हालांकि कई बार छुट्टी वाले दिन बाजार में स्पेशल ट्रेडिंग होती है। आज भी स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा ही होने वाला है। बीते दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के अनुसार आज मॉक ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार एक्सचेंज एक घंटे के लिए खुलेगा।

नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market) हर शनिवार और रविवार को बंद रहता है। लेकिन कई बार स्पेशन ट्रेडिंग सेशन (Special Trading Session) की वजह से बाजार खुला रहता है। आज भी वैसा ही हो रहा है। जी हां, आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में ट्रेडिंग सेशन होगा। एनएसई ने इसकी जानकारी कल बाजार बंद होने के बाद दी थी।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सर्कुलर के अनुसार 28 सितंबर 2024 (शनिवार) यानी आज Mock Trading Sessions के तहत बाजार खुला रहेगा। बता दें कि इससे पहले भी कई बार स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के लिए छुट्टी वाले दिन शेयर बाजार खुले हैं।

कैपिटल मार्केट सेगमेंट में होगी ट्रेडिंग

एनएसई के सर्कुलर के अनुसार 28 सितंबर को कैपिटल मार्केट सेगमेंट में मॉक ट्रेडिंग सेशन होगा। इसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) में भी ट्रेडिंग होगी। इस ट्रेडिंग के दौरान डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच-ओवर कर दिया जाएगा। दरअसल, आपात स्थिति में स्टॉक एक्सचेंज की सर्विस पर कोई असर न पड़े इसके लिए स्विच-ओवर किया जाता है।

क्या है ट्रेडिंग का समय

आज दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच एनएसई की इमरजेंसी चेकिंग होगी। दरअसल, यह एक टेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन (Testing TR=rading Session) है। इसका उद्देश्य है कि इमरजेंसी में एनएसई की सर्विस सुचारु रूप से जारी रहे। आज के मॉक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन डिजास्टर रिकवरी साइट से होगी। इस साइट के जरिये सिस्टम की रिएक्टिविटी का आंकलन किया जाएगा। बता दें कि किसी भी क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए डिजास्टर साइट काफी महत्वपूर्ण है।

T+0 सेटलमेंट सिस्टम से नहीं हटा ब्रेक

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने T+0 सेटलमेंट सिस्टम पर रोक लगाई है। वैसे तो यह रोक 30 सितंबर से लागू होना था, लेकिन एनएसई ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि फिलहाल T+0 सेटलमेंट सिस्टम पर रोक है। स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिफिकेशन में जानकारी दी है कि यह सिस्टम को कब लागू किया जाएगा।

कैसा था पिछले सत्र का कारोबार

इस पूरे हफ्ते शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। 27 सितंबर 2024 को भी शेयर मार्केट के दोनों सूचकांक अपने उच्चतम स्तर पर खुले थे। लेकिन, बाद में यह दोनों लाल निशान पर बंद हुए। बीते सत्र में सेंसेक्स 264.27 अंक गिरकर 85,571.85 अंक पर आ गया। निफ्टी भी 40.90 अंक गिरकर 26,175.15 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ।

फेस्टिव सीजन से पहले रियल एस्टेट सेक्टर में खुशी, अन्डर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मांग में हुई बढ़ोतरी

परिवहन विशेष न्यूज

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। ऐसे मेंरेडी-टू-मूव हाउसिंग यूनिट्स के मांग में बढ़ोतरी देखने को मिला है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट विश्वास बुनियादी ढांचे के विकास फ्लेक्सी पेमेंट प्लान जैसे कारकों की वजह है। अन्डर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मांग में बढ़ोतरी को लेकर दिग्गजों ने रिएक्शन दिया है।

नई दिल्ली। रेडी-टू-मूव हाउसिंग यूनिट्स की बढ़ती मांग और लग्जरी संपत्तियों बिक्री में शानदार तेजी देखने को मिली है। निर्माणाधीन प्रॉपर्टी रेडी-टू-मूव की तुलना में किफायती हैं। ऐसे में लोग रेडी-टू-मूव पसंद कर रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट, विश्वास, बुनियादी ढांचे के विकास, फ्लेक्सी पेमेंट प्लान, निर्माण तकनीकों और प्रोजेक्ट कठोर निगरानी यानी नियामक कार्रवाई का मिश्रण है।

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास, मेट्रो कॉरिडोर और रेलवे नेटवर्क का विस्तार, रैपिड रेल सचालन, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क को जोड़ना, समर्पित विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों ने इन स्थानों को भारत का एक निवेश केंद्र बना दिया है जहां घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश कर रही हैं।

क्या है दिग्गजों का रिएक्शन

निराला वर्ल्ड के सीएमडी, श्री सुरेश गर्ग ने कहा कि भवन निर्माण की उन्नत तकनीकों को अपनाकर हमने समय से पहले अपने अगले चरण पूरे कर लिए है। निर्माण की गुणवत्ता और गति को देखते हुए, हमें खरीदारों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री संख्या अच्छी रही।

इरोज ग्रुप के निदेशक अवनीश सूद के अनुसार शुरुआत से ही हम अधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं और विश्वास के प्रतीक के रूप में हमने संपूर्णम के अपने अंतिम चरण को पूरा कर लिया है। इसके अलावा हमारे आकार और लागत के कारण हमें हमारे नए लॉन्च किए गए संपूर्णम 3 को लेकर अच्छा रिस्पांस मिला है।

अक्टूबर में एलपीजी सिलेंडर के साथ बदल जाएंगे पैसे से जुड़े कई नियम, आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर

Rule Change अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने कई फाइनेंशियल कामों की डेडलाइन है। हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय नियम बदल जाते हैं। अक्टूबर में भी ठीक ऐसा ही होगा। 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम के साथ पीपीएप और सुकन्या योजना के नियमों में बदलाव होगा। इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।...

नई दिल्ली। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और जल्द ही अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा। महीने के पहले दिन से कई वित्तीय नियमों में बदलाव हो जाएगा। इन नियमों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर के महीने से कौन- से फाइनेंशियल रूल्स बदलने वाला है।

गैस सिलेंडर

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। तेल कंपनियां घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम अपडेट करते हैं। सितंबर में तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर (Commercial Cylinder) के दामों में इजाफा किया था।

शेयर बायबैक

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव 1 अक्तूबर 2024 से लागू होगा। नए नियमों के अनुसार अब डीमैट अकाउंट (Demat Account) में शेयर 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। वहीं, रिकॉर्ड डेट के दो दिनों के भीतर ही निवेशकों को बोनस शेयर (Bonus Share) मिल जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना

अगर आपकी बेटी के नाम से सुकन्या अकाउंट (Sukanya Account) है तो बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से इसके नियम बदल गए। अगर दादा-दादी या फिर कोई दूसरा व्यक्ति ने सुकन्या अकाउंट ओपन किया है तो अकाउंट को माता-पिता या अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। अगर सुकन्या अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।

पीपीएफ के नियमों में बदलाव

केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट रखने पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट (Post Office Saving Account) पर 18 साल से कम उम्र के खाताधारक को ब्याज नहीं मिलेगा। जब उनकी आयु 18 साल की हो जाएगी तो उसके बाद ब्याज क्रेडिट होगा।

फेस्टिव सीजन से पहले आसमान छू रहा है सोना, इन वजह से बढ़ रही है कीमत

Gold Rates भारत में सोना खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। महिलीओं को सोना खरीदना काफी पसंद है। जहां एक तरफ सोना सुंदरता में चार चांद लगाता है वहीं दूसरी तरफ यह निवेश के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर सोने की कीमतों की बात करें तो इस साल सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हम आपको इस आर्टिकल में सोने की कीमतों के बढ़ने की वजह बताएंगे।

नई दिल्ली। फेस्टिवल सीजन में सोने (Gold) की खरीदारी में तेजी आती है। दीवाली से पहले धनतेरस पर लोग सोना-चांदी जैसे महंगी धातु खरीदना पसंद करते हैं। अभी त्योहारों का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ और उससे पहले ही सोने के भाव आसमान छूने लगे। ऐसे में खरीदारों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर सोने की कीमतों में क्यों तेजी आ रही है और इसके भाव में कबतक नरमी आ सकती है।

क्या है सोने का भाव (Gold Price)

सर्राफा बाजार में सोने के दाम में आज भी तेजी देखने को मिली है। भारत में सोना 77,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। अगर आज सोने की कीमत की बात करें तो राजधानी दिल्ली में सोना 77,985.00 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। ऐसे ही कई राज्यों में सोने की कीमत बढ़ गई है।

क्यों महंगा हो रहा है सोना

सोने की कीमतों में तेजी आती है, लेकिन इस साल इनकी कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। 1 जनवरी को जहां दिल्ली में सोना 65,000 रुपये था वह अब 77,000 रुपये के पार पहुंच गया है। अगर सोने की कीमतों में तेजी की वजह जानें को मुख्य वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन है।

वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक की वजह से निवेशक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने में निवेश करते हैं जिसकी वजह से सोने की मांग बढ़ जाती है और इसके दाम में भी इजाफा हो रहा है। वहीं, फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद से भी सोने की कीमतों में तेजी आई। 18 सितंबर को फेड ने ब्याज दरों में 0.50 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया। फेड के फैसले के बाद डॉलर में नरमी आई और यह 100.51 पर आ गया। डॉलर के मूल्य में गिरावट भी सोने की कीमतों में इजाफा होने की वजह है।

कब तक सस्ता होगा सोना

गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों आस लगाए बैठे हैं कि सोने के दाम में कब नरमी आएगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अनुसार इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष और लेबनान में स्थिति बिगड़ने की वजह से गोल्ड की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद नहीं है। निवेशक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने में धड़ाधड़ निवेश कर रहे हैं। ऐसे में अभी गोल्ड की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद दिख रही है।

ओपन एआई विवादों में घिरा, मीरा मुराती के इस्तीफे के बाद दो हाई-प्रोफाइल पर्सन ने भी दिया रेजिग्नेशन

OpenAI की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी मीरा मुराती ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कंपनी के दो अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों बॉब मैकग्रे (मुख्य अनुसंधान अधिकारी) और बैरेट ज़ोफ़ (अनुसंधान के उपाध्यक्ष) को भी निकाला गया। ये सब होने के बाद OpenAI विवादों में घिर गया है। दरअसल माना जा रहा है कि OpenAI खुद को सार्वजनिक लाभ निगम के रूप में पुनर्गठित करने की सोच रहा है।

नई दिल्ली। आर्टिफिशेयल इंटेलिजेंस का नाम जब भी आता है तो OpenAI का जिक्र होता ही है। OpenAI एक तरह की नॉन-प्रॉफिट इंटेटिटी है। अब कंपनी के दो उच्च-स्तरीय कार्यकारी ने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद कंपनी विवादों में घिर गई है। दरअसल, कंपनी ने संकेत दिया है कि वह प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनेगी। इस संकेत के बाद विवाद खड़ा हो गया है।

कई संगठनों का कहना है कि अगर OpenAI भी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनती है तो कंपनी अपने AI उद्देश्यों से दूर जा सकती है।

2015 में शुरू हुआ था OpenAI

OpenAI की स्थापना नॉन-प्रॉफिट संस्था के रूप में वर्ष 2015 में हुई थी। साल 2019 में कंपनी ने एक लाभ-आधारित सहायक कंपनी की शुरुआत की थी। इसमें सर्विस के साथ-साथ बाहरी निवेश को भी अनुमति दी गई। इसमें निवेशख और कर्मचारी दोनों को एक निश्चित सीमा तक रिटर्न मिलता था।

कैसे शुरू हुआ विवाद

OpenAI का विवाद तह शुरू हुआ जब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी Microsoft ने निवेश किया। इस निवेश ने कंपनी के मुनाफे की ओर संकेत किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी सार्वजनिक लाभ निगम में पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है। कंपनी के इस विचार पर अटकलें लगाया जा रहा है कि कंपनी वित्तीय चुनौतियों के समाधा के लिए यह फैसला लेगी। माना जा रहा है कि OpenAI का खर्च बहुत बड़ गया है, इस वजह से चालू वित्त वर्ष में कंपनी को 5 बिलियन डॉलर तक का घाटा हो सकता है।

अगर कंपनी सार्वजनिक लाभ निगम के रूप में पुनर्गठित होता है को कंपनी सुरक्षित एआई विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को खतरे में डाल सकता है। आलाचकों का कहना है कि मुनाफे की चाहत में कंपनी एआई सिस्टम को तैनात करने की दिशा में आक्रामक प्रयास कर सकती है। दरअसल, OpenAI की स्थापना एआई प्रौद्योगिकियों की नैतिक उन्नति को प्राथमिकता देने के लिए हुई थी।

दो उच्च-स्तरीय कार्यकारी ने दिया इस्तीफा

OpenAI के उच्च-स्तरीय कार्यकारी के इस्तीफे ने भी कंपनी को विवादों में खड़ा कर दिया है। हाल में कंपनी की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी मीरा मुराती इस्तीफा दिया है। मीरा मुराती के इस्तीफे के बाद दो अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों, बॉब मैकग्रे (मुख्य अनुसंधान अधिकारी) और बैरेट ज़ोफ़ (अनुसंधान के उपाध्यक्ष) भी कंपनी से बाहर निकल गए।

बता दें कि OpenAI की जीपीटी-4 मॉडल के शुभारंभ में मीरा मुराती की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मीरा मुराती ने इस्तीफा देते हुए कहा कि पिछले वर्ष अन्य सह-संस्थापक और वरिष्ठ शोधकर्ता ने कंपनी छोड़ दिया था। दरअसल, OpenAI लाभ-प्राप्त व्यवसाय मॉडल की ओर बढ़ रही है। ऐसे में कर्मचारी कंपनी छोड़ रहे हैं।

ट्रेन में चाहिए लोवर बर्थ सीट, टिकट बुकिंग के समय जरूर अपनाएं ये आसान ट्रिक

भारतीय रेलवे में रोज लाखों लोगों सफर करते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे पूरी कोशिश करता है कि वह अपने यात्रियों का सफर आरामदायक बनाए। कई यात्री भारतीय रेलवे के कई नियमों से अनजान है। भारतीय रेलवे अपने सभी यात्री को सुविधा देता है कि वह अपनी बर्थ चॉइस बताएं। हम आपको इस आर्टिकल में भारतीय रेलवे के इस नियम के बारे में बताएंगे।

नई दिल्ली। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या की बात करें तो दिन में लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। लोकल ट्रेन के साथ पैसेंजर ट्रेन भी लगभग हमेशा भरी रहती है। ऐसे में कई बार लोगों को ट्रेन में वेटिंग टिकट लेकर सफर करना पड़ता है। कई यात्री को लगता है कि भारतीय रेलवे में सीट सेलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि, ये गलत है। हम आपको आज भारतीय रेलवे के एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसके जरिये आप भी कन्फर्म लोअर सीट पा सकते हैं।

किस मिलता है लोअर बर्थ

वैसे तो भारतीय रेलवे सीनियर सिटिजन को सबसे पहले लोअर बर्थ अलॉट करता है। जी हां, भारतीय रेलवे में रिजर्व लोअर सीट का कोटा होता है। यह कोटा केवल सीनियर सिटिजन के लिए लागू है। इसका मतलब है कि भारतीय रेलवे सबसे पहले सीनियर सिटिजन को लोउर बर्थ सीट देता है। रिजर्व लोअर सीट का कोटा केवल तब ही लागू होता है जब कोई सीनियर सिटिजन अकेले सफर कर रहा है या फिर एक साथ दो सीनियर सिटिजन सफर कर रहे हैं।

अगर दो से ज्यादा सीनियर सिटिजन एक साथ सफर कर रहे हैं तब लोअर सीट का रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। अगर किसी सीनियर सिटिजन को अपर या मिडिल बर्थ मिला है तो वह टिकट चेकिंग स्टाफ से कहकर उसे चेंज करने की रिक्वेस्ट दे सकता है।

गीता के उपदेशों और श्रीकृष्ण के जीवन से प्रेरणा

प्रिय बच्चों,
सादर नमस्कार!

मैं अंकुर, आपको इस पत्र के माध्यम से जीवन के उन महत्वपूर्ण सबक और आदर्शों से अवगत कराना चाहता हूँ, जिन्हें आप अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। ये सबक महाभारत के गीता के उपदेशों और भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े हैं। गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं।

1. कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करोः भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में बताया है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यह सीख आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगी। चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, या कोई अन्य कार्य – पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य करें, सफलता स्वतः आपके पास आएगी।

2. सच्चाई और ईमानदारी का पालन करोः श्रीकृष्ण के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व हमेशा रहा है। हर स्थिति में सत्य के मार्ग पर चलना आपको मजबूत और आत्मविश्वासी बनाएगा। यह गुण आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

3. आत्म-विश्वास और धैर्य रखोः श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से यह सिखाया कि आत्म-विश्वास और धैर्य जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियाँ कठिन हैं, तब श्रीकृष्ण की इस शिक्षा को याद रखें कि धैर्य और आत्म-विश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।

4. अहंकार से दूर रहोः गीता में कहा गया है कि अहंकार इंसान को उसके सत्य मार्ग से दूर कर देता है। श्रीकृष्ण ने हमें सिखाया है कि विनम्रता और नम्रता से ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा दूसरों का सम्मान करें और विनम्र रहें।

5. अपने कर्तव्यों का पालन करोः भगवान श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में विभिन्न भूमिकाएँ निभाई, चाहे वह एक मित्र, राजा, या गुरु के रूप में हो। उन्होंने हर बार अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन के हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए।

6. हर परिस्थिति में समभाव रखोः जीवन में सुख और दुःख आते-जाते रहते हैं। श्रीकृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें हर परिस्थिति में समभाव रखना चाहिए। न तो खुशी में ज्यादा उत्साहित होना चाहिए, और न ही दुख में निराश। संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची कुंजी है।

7. मित्रता और सहयोगः श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में धन-दौलत या पद का कोई महत्व नहीं होता। सच्चे मित्र हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अपने मित्रों का साथ दें और उनकी मदद करें।

8. पर्यावरण से प्रेम करोः श्रीकृष्ण का बाल्यकाल वृंदावन में गौचारण और प्रकृति के सान्निध्य में बीता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।

प्रिय बच्चों, आप सभी देश का भविष्य हैं। गीता के उपदेशों और श्रीकृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को दिशा दें। इससे न केवल आप अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

मेरी यही कामना है कि आप सभी जीवन के इन आदर्शों को अपनाएं और एक सुखद, समृद्ध और नैतिक जीवन की ओर अग्रसर हों।

सप्रेम,
डॉ. अंकुर शरण
संस्कारशाला

'न्याय प्रणाली दिव्यांग बच्चों की बढ़ती हुई कमजोरियों को समझे', बाल सुरक्षा पर आधारित कार्यक्रम में बोले CJI चंद्रचूड़

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्याय प्रणाली पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक दिव्यांग बच्चों की कमजोरियों को समझे और उन पर कार्रवाई करे। दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियां भौतिक पहुंच के मुद्दों से कहीं अधिक हैं। उन्हें उन सामाजिक पूर्वाग्रहों के अलावा रूढ़ियों तथा गलत धारणाओं से भी निपटना होगा

नई दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्याय प्रणाली पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक दिव्यांग बच्चों की कमजोरियों को समझे और उन पर कार्रवाई करे।

दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियां भौतिक पहुंच के मुद्दों से कहीं अधिक हैं। उन्हें उन सामाजिक पूर्वाग्रहों के अलावा रूढ़ियों तथा गलत धारणाओं से भी निपटना होगा, जो जीवन के लगभग हर पहलू में व्याप्त हैं। सीजेआई ने बाल संरक्षण पर नौवें वार्षिक राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के अवसर पर यह बात कही।

अदालतों तक की न्याय प्रणाली इन बच्चों की कमजोरियों को समझे

दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति के तत्वावधान में यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक की न्याय प्रणाली इन बच्चों की बढ़ती हुई कमजोरियों को समझे और उस पर कार्रवाई करे।

जब हम किशोर न्याय के बारे में बात करते हैं, खासकर दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में, तो हम अंतर्संबंध की अवधारणा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दिव्यांगता अक्सर लिंग, जाति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जातीयता जैसी अन्य पहचानों के साथ जुड़ती है। इससे बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। अंतर्संबंध का सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कई तरह की पहचान भेदभाव का अनुभव कराने के लिए एक दूसरे से मिली होती हैं।

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी : मंत्रीमहिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को क्षमता निर्माण के महत्व और ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता जैसे मुद्दों के समाधान पर जोर दिया।

ये युवक दिल्ली से आते हैं और आरटीओ जैसी गाड़ियों को रोक कर वसूली करते हैं

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर् : सड़क सुरक्षा के नाम पर बटी ले रही है । जालसाज दिल्ली से आकर सुंदरगढ़ में वसूली कर रहे हैं ।वह फिर से पुलिस सुरक्षा क्षेत्र में है। 10वें राज्य राजमार्ग के पास सुंदरगढ़ भस्म थानाकुंडुकेला ट्रक ड्राइवरों से दान इकट्ठा करने के लिए दोनों तरफ खुला है। जालसाज लाल रेडियम का छोटा सा टुकड़ा पहनकर पैसे मांग रहा है। दो प्रकार की रसीदें. गुलाबी रंग में 100 रुपये, पीले रंग में 2000 रुपये और नीले रंग में 300 रुपये। एक और स्टीकर जिस पर शराब लिखा है, पार्टी इसके लिए 500 रुपये चार्ज कर रही है।

इसमें कहा गया है कि रसीद जारी होने के बाद यह दो महीने के लिए वैध है। यह बड़ी बात है कि इस जालसाज के बारे में न तो पुलिस को और न ही परिवहन विभाग को कोई खबर है। सड़क सुरक्षा शिविर के नाम पर लूट मची हुई है। ट्रकों को जबरन रोका जा रहा है, रेडियोग्राफी की जा रही है और रसीदें वसूली जा रही हैं ।रात में जब कोहरा होता है तो रेडियम्लगा रहा है । हालांकि, उनके पास न तो परिवहन विभाग से अनुमति है और न ही पुलिस से। ये युवक दिल्ली से आते हैं और आरटीओ जैसी गाड़ियों को रोक कर वसूली करते हैं। घटना के संबंध में आरटीओ विभाग से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

लॉन्चिंग के लिए तैयार क्रू-9 मिशन, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की होनी है वापसी; क्या है NASA की पूरी प्लानिंग?

परिवहन विशेष न्यूज

आठ दिन के स्पेस मिशन पर गईं सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर को तीन महीने से अधिक समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हो गया है। अब नासा और स्पेसएक्स के क्रू-9 मिशन से उन्हें वापस लाने की तैयारी है। हालांकि इसकी भी लॉन्चिंग टल गई थी लेकिन अब यह उड़ान भरने के लिए तैयार है। जानिए क्या है नासा की आगे की योजना है।

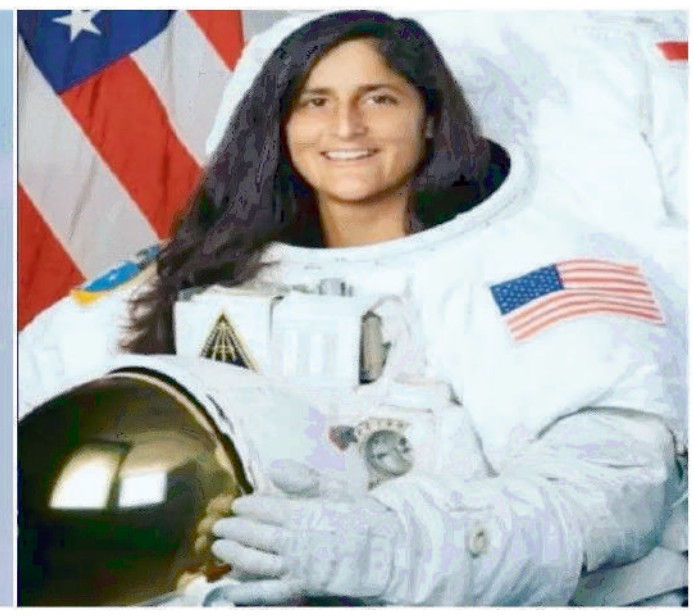

नई दिल्ली। नासा और स्पेसएक्स का क्रू-9 मिशन अंतरिक्ष में फंसे भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाएगा। क्रू-9 मिशन को शुरू में 26 सितंबर को लांच करने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर तूफान हेलेन से मौसम की स्थिति काफी खराब हो गई थी।

इसी वजह से मिशन को टाल दिया गया था। सुनीता और विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा के निक हेग और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनाट अलेक्जेंडर गोरबुनोव मिशन पर जा रहे हैं।

पांच महीने स्पेस स्टेशन में रहेंगे

दोनों को पांच महीने के मिशन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) भेजा जा रहा है। हेग और गोरबुनोव अगले क्रू रोटेशन के साथ फरवरी तक आईएसएस पर रहेंगे। अंतरिक्ष यात्री जेना कार्डमैन और स्टेफनी विल्सन भी शुरू में क्रू-9 मिशन का हिस्सा थे, लेकिन उनको वापस आने वाले यात्रियों की जगह न होने की वजह से हटा दिया गया था।

आठ दिन का था मिशन

गौरतलब है कि शुरुआत में आठ दिन के लिए स्पेस मिशन पर गए सुनीता और बुच विल्मोर को तीन महीने से अधिक समय हो गया है। उनको लेकर गए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उसे खाली ही पृथ्वी पर वापस बुला लिया गया। ऐसे में स्पेसएक्स के क्रू-9 मिशन से अब दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी होगी।

अच्छे दिन आएंगे की बड़ी उम्मीद के साथ जरूरतमंद ग़रीब लोगों ने भाजपा को सिर आंखों पर बैठाया लेकिन दस साल बाद भी ग़रीब जरूरतमंद वर्ग महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से त्रस्त हैं : ठाकुर संजीव कुमार

- भाजपा के सांसद, विधायक और जिम्मेदार को जरूरतमंद ग़रीब जनता की कोई चिंता नहीं : ठाकुर संजीव कुमार सिंह

- भाजपा के 10 साल के राज में किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, बेरोजगार, कर्मठ कार्यकर्ता, सब परेशान : ठाकुर संजीव कुमार सिंह

नई दिल्ली, संजय साग़र सिंह। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता एआइसीसी, वरिष्ठ समाजसेवी ठाकुर संजीव कुमार सिंह ने भाजपा द्वारा की जा रही गलतियों और नाकामियों को गिनाते हुए कहा, अच्छे दिन आएंगे की बड़ी उम्मीद के साथ जरूरतमंद ग़रीब लोगों ने भाजपा को सिर आंखों पर बैठाया, लेकिन आज ग़रीब जरूरतमंद वर्ग महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भाजपा ने दस सालों में अंतिम पायदान पर खडे कमजोर असहाय जरूरतमंद ग़रीब वर्ग के कल्याण के लिए कुछ नहीं हुआ। आज़ जरूरतमंद ग़रीब आदमी, सरकार द्वारा चलाई जा रहीं आयुष्मान, उज्ज्वला आदि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पाने ले लिए सांसद, विधायक और जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से दर-दर भटक ने को मजबूर हैं, लेकिन भाजपा के दस साल बाद भी कुछ सांसद, विधायक और जिम्मेदार अपना स्वागत सम्मान करने में और स्टारों के साथ फोटों खींचने में व्यस्त हैं। इनको सत्ता तक पहुंचाने वाले भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं सहित जरूरतमंद गरीबों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही हैं। कई जगह तो ऐसी हैं, जहां जनता को सिर्फ़ पानी के पांच पांच दिन तरसाया जा रहा हैं और दलित बस्तियों भेदभाव के कारण विकास के वंचित हैं। वहीं, चिकित्सा, शिक्षा सहित सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर हैं। आज़ भाजपा के दस साल के शासन में सांसद, विधायक और जिम्मेदारों की लापरवाहियों के कारण किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, बेरोजगार, कर्मठ कार्यकर्ता सब परेशान है।

उन्होंने कहा, बहुत खेदपूर्ण है कि भाजपा के कुछ नेता नेता झूठी बातों के बाजीगर हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होने झूठ बोलकर ठगा नहीं। ये राजनीति में न आए होते तो फिल्मों एवं टीवी सीरियलों की पटकथा में भी सफल हो सकते थे। केवल भाजपा नेता ही खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए चुनावी पटल पर जनता से बड़े बड़े सफेद झूठ बोलने के बाद नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन इन्होने ही ख़ुद सुबह शाम ग़रीब जनता से झूठ बोलकर लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को तार-तार किया हैं। और एक वार फिर भाजपा जुमला मंडली अपने लच्छेदार भाषणों में झूठे वादों व जुमलों की झड़ी लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अपने दो कार्यकाल के दौरान इनकों जरूरतमंद गरीबों की याद नहीं आई।

हमारे देश में आज़, बेलगाम महंगाई, बेरोजगारी, भष्टाचार मुख्य मुद्दे हैं। अब खोखले झांसों से पिछड़ों, ग़रीब दलितों और जनता का ध्यान भटकाया नहीं जा सकता। बेलगाम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा साबित होने जा रहा है। तेल, आटा, दाल, मसाले, सब्जियों, गैस सिलेंडर, फलों आदि दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर ग़रीब जनता में भाजपा के प्रति खासी नाराजगी दिखाई दे रही हैं। अधिकांश ग़रीब लोगों का मानना है कि भाजपा ने चुनावी खर्चों को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करने बाले व्यापारियों व काला बाजारियों को खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा, भाजपा 10 साल से हर चुनाव में नए- नए दावे तो करती है लेकिन भाजपा को अंतिम पायदान पर खडे कमजोर असहाय ग़रीब की बेसिक सुविधाओं की भी चिंता नहीं हैं। अब चुनाव आते ही भाजपा नए सब्जबाग लेकर फिर से जनता के बीच आ गई। समझ नहीं आता है कि यह कैसे जनता से बोट मांग रहे हैं। दस सालों में उन्होंने ग़रीब लोगों को परवाह नहीं की, अब पांच साल में शहर में बदलाव का झूठा वादा लेकर आ गए। इन्होने दस साल सिवाय झूठ बोलने के अलाबा कुछ नहीं किया, वह आगे क्या करेंगे? निचले पायदान पर खडे कमजोर असहाय जरूरतमंद ग़रीब लोग समझ सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, दस साल तक मोदीजी और योगीजी के चहरे पर ग़रीब जनता के वोट से सत्ता का सुख भोग रहे भाजपा के सांसद विधायकों के पास जनता को बताने और दिखाने को कुछ नहीं है। अपने कुशासन से भाजपा के सांसद और विधायकों ने देश व प्रदेशों का बेड़ा गर्ग कर दिया। इससे मुक्ति के लिए पिछड़े, दलित और ग़रीब जनता केवल चुनावों का इंतजार कर रहे है, ताकि वोट की चोट से भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, लेकिन भाजपा सरकार गरीबों की समस्याओं पर ध्यान ना देकर सुविधाएं देने की जगह उल्टा, ग़रीब दलितों, पिछड़ों और ग़रीब जनता की बात को दबाने के लिए देश की सभी सरकारी गैर सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग करने में जुटी है। कोर्ट भी इस चीज को लेकर टिप्पणी कर चुकी है, लेकिन मंत्री, सांसद और विधायक बाज नहीं आ रहे। दलितों, पिछड़ों और ग़रीब जनता की आवाज़ उठाने बाले राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को जांच एजेंसियों का डर दिखाकर प्रताड़ित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अब भाजपा के दिन लद गए हैं और दलितों, पिछड़ों और ग़रीब जनता की आवाज़ उठाने बाली पार्टियों का समय आने वाला है और आने वाले समय में जल्द बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि पिछले 10 सालों के राज में भाजपा के सांसद, विधायक और जिम्मेदार की असलियत दलितों, पिछड़ों और ग़रीब जनता के सामने आ चुकी है। भाजपा हमेशा केंद्र व राज्य में सरकारों को डबल इंजन की सरकार बताती रही। इन सरकारों के भाजपा के सांसद, विधायक और जिम्मेदार ने अपनी मनमानी और लापरवाही से देश-प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। आज हर वर्ग महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त है लेकिन भाजपा के सांसद, विधायक और जिम्मेदारों ने अंतिम पायदान पर खडे कमजोर असहाय ग़रीब दलित पिछड़ों की परवाह नहीं की और ना उन्हें मिलने वाली बेसिक सुविधाओं की चिंता की, जब इन भाजपा के सांसद, विधायक और जिम्मेदार ने जनता की चिंता नहीं की तो आने वाले चुनावों में ग़रीब जनता भी इनकी चिंता नहीं करेगी। भाजपा के सांसद, विधायक और जिम्मेदार को उनके किए की सजा चुनाव में देकर सबक सिखाएगी। क्योंकि झूठे को सजा देना कानूनी धर्म है। गरीब जनता भी भाजपा को उसके झूठ की सजा आज़ नहीं तो कल जरूर देगी। गरीबों से वोट लेकर लोगों को दस साल तक परेशानियों में रखने का कार्य भाजपा ने किया है। अब बोट की चोट भाजपा के सांसद, विधायक और जिम्मेदार के लिए सबसे बड़ी सजा होगी।

तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सहलाकर समिति में गैर सरकारी सदस्य मनोनीत गौरी सीरवी

रायपुर मारवाड़ देवली कलां सोजत विधायक श्रीमती शोभा जी चौहान की अनुशंसा से राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा रायपुर तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्य मनोनीत होने पर उम्मीद है कि समिति में आपकी सदस्यता सहभागिता से राजस्थान सरकार एवं विधायक जी की मशां अनुसार खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में आमजन को राहत मिलेगी !

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023